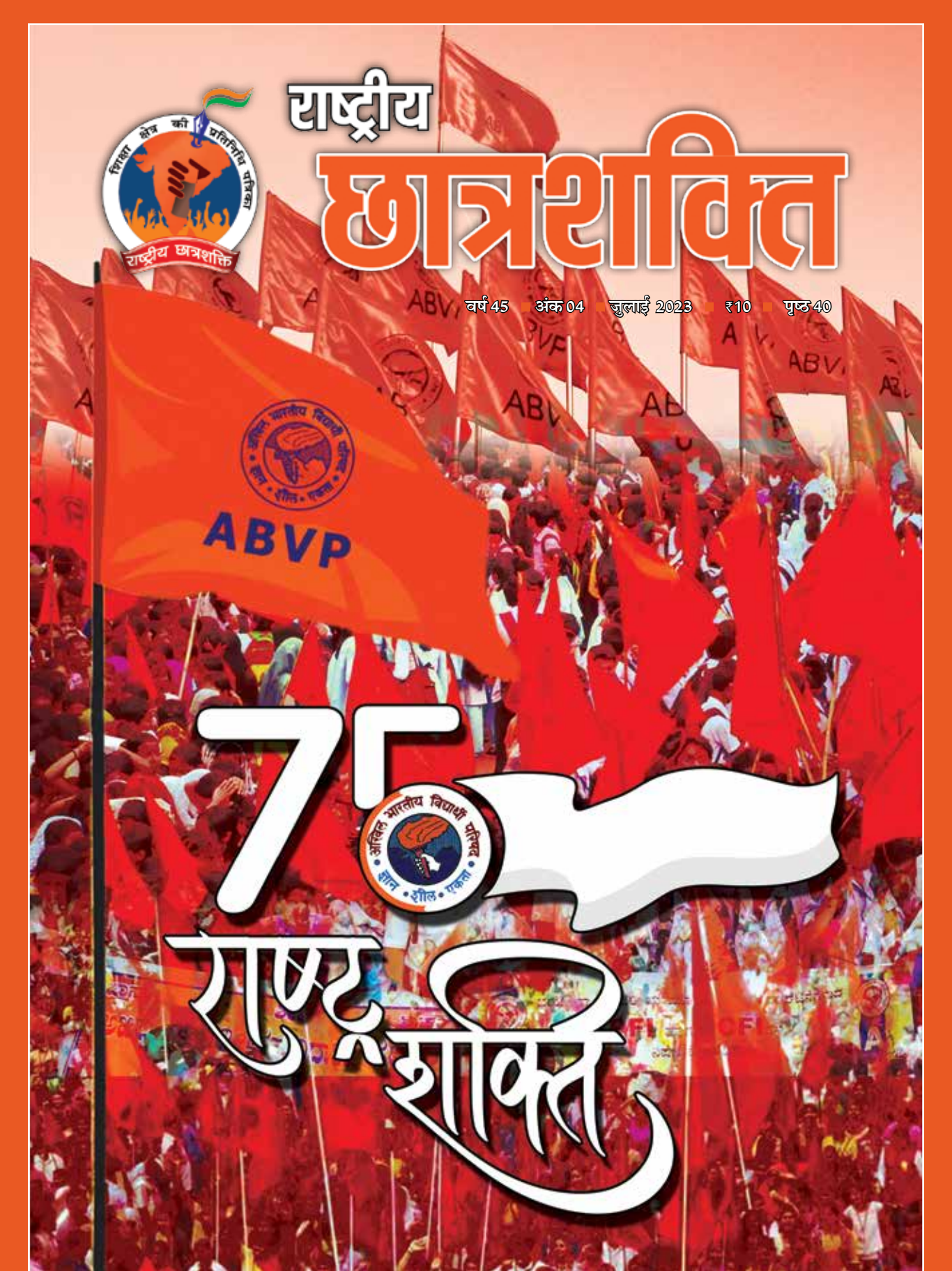

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 45 ▪ अंक 04 ▪ जुलाई 2023 ▪ ₹10 ▪ पृष्ठ 40

गुवाहाटी : दीप प्रज्ज्वलित कर अभाविप अमृत महोत्सव समारोह का उदघाटन करते हुए असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, रा.स्व.संघ के अ. भा. प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान व अन्य

जगन्नाथपुरी : रथयात्रा के दौरान ग्रीन कोरिडोर बनाकर एंबुलेंस को निकालते हुए अभाविप ओड़िसा के कार्यकर्ता

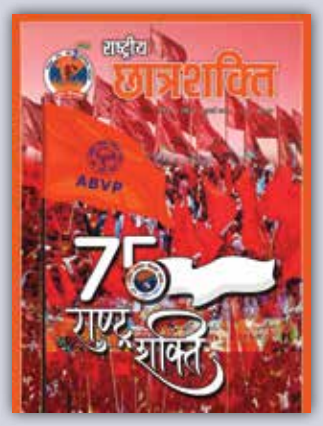

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 45, अंक 04
जुलाई 2023

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ध्येय यात्रा

विश्व के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए हुए जनप्रयासों के इतिहास में विद्यार्थी-युवा आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत...

संपादकीय	04
मेरी पहचान के निर्माण में अभाविप का महनीय योगदान : राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया	11
शिक्षा की प्रक्रिया से न तो कोई छात्र छूटे और न ही कोई टूटे : राजशरण शाही	12
विज्ञान अध्येतावृत्तियों में बढ़ोत्तरी का अभाविप ने स्वागत किया	13
UNIFORM CIVIL CODE – A STEP TOWARDS HARMONY AND SOCIAL COHESION	14
खेल गतिविधि आयाम द्वारा महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन, रानी लक्ष्मीबाई टीम विजयी घोषित	16
अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण के मामले में जांच की मांग कर रही है अभाविप	17
गीता प्रेस को मिले शांति पुरस्कार के विरोध में उतरे छद्म हिंदूवादी	18
अमर बलिदानी सिदो–कान्हू की याद में अभाविप (झारखण्ड) ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम	19
अभाविप द्वारा आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम में छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर	20
बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाने पर कई राज्य सहमत	22
VISAKHAPATNAM: ABVP STAGES MOCK FUNERAL AGAINST HIGH EDUCATIONAL FEES	23
प्रशासनिक सक्रियता के कारण विपर्जय चक्रवात से नहीं हुई जनहानि	24
विपर्जय चक्रवात से प्रभावित जनता की सेवा में जुटी अभाविप	25
GLOBAL MOVEMENT FOR MODERATING ISLAM IS INEVITABLE	26
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक को स्वीकृति देने का निर्णय स्वागतयोग्य : अभाविप	28
अभाविप आयाम जिज्ञासा द्वारा आषाढ़वारी चिकित्सा सेवा–2023 का आयोजन	29
'परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स–2.0 की रिपोर्ट ने खोली दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की पोल'	30
छात्रा के साथ सहायक प्राध्यापक ने की अभद्रता, सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अभाविप ने किया प्रदर्शन	31
अभाविप ने देश के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया	32
ABVP DEMANDS FORMATION OF EXAMINATION DEPARTMENT FOR PERMANENT SOLUTION OF PROBLEMS OF SOL STUDENTS	33
अभाविप ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव, दिल्ली में चल रहे कोचिंग संस्थानों के नियमन की मांग	34
रथयात्रा में आए श्रद्धालुओं के लिए सेवा कार्य में जुटे अभाविप कार्यकर्ता	35
गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर अभाविप का प्रदर्शन, उच्च शिक्षा मंत्री ने दौरा रद्द किया	36
शिक्षकों से राष्ट्र प्रथम भाव के साथ आगे आने की अपील	37
शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण : अभाविप	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी यात्रा का एक पड़ाव और पार कर लिया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्रीय विचार से ओत-प्रोत देश के छात्र-युवाओं की पहल पर अभाविप का कार्य तो प्रारंभ हो गया था, किन्तु उसे संवैधानिक रूप देकर पंजीकृत कराने का काम 9 जुलाई 1949 को हुआ। इसे ही परिषद अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। 9 जुलाई 2023 को इसने अपने अमृतकाल में प्रवेश किया है।

एक दृष्टि से देखें तो परिषद की यह 75 वर्षों की यात्रा स्वाधीन भारत की यात्रा के साथ-साथ चली है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्रीय विचार के आग्रही प्रतिपादन तथा समसामयिक प्रश्नों पर सुविचारित मत को दृढ़ता के साथ रखने की विशिष्ट कार्यपद्धति के कारण परिषद को जहां अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, वहीं इस कठिन समय में बिना किसी समझौते के सिद्धांतों पर डटे रहने के स्वभाव के कारण यश भी प्राप्त हुआ है।

'छात्रशक्ति-राष्ट्रशक्ति' एवं 'आज का छात्र-आज का नागरिक' जैसी स्थापनाएं अभाविप को अन्य पेशेवर छात्र संगठनों से अलग करती हैं। सेवा, समरसता और अंत्योदय जैसे शब्द जहां अन्य छात्र-संगठनों की शब्दावली में आज तक स्थान नहीं पा सके हैं, वहीं परिषद की पूरी कार्यपद्धति के केन्द्र में यही विचार हैं। राजनीतिक दलों के भर्ती केन्द्र के रूप में जहां अन्य छात्र-संगठन काम करते हैं, वहीं विद्यार्थी परिषद दल और सत्ता की राजनीति से परे स्वयंपूर्ण, स्वायत्त, स्वावलम्बी संगठन के रूप में उभरा है।

निरंतर बदलती कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को इन विशेषताओं और मूल्यों के साथ संकल्पबद्ध करते हुए एक स्थायी संगठन को गढ़ने के काम में असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपाया है। अमृतकाल में प्रवेश के अवसर पर उन समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति श्रद्धानत होना स्वाभाविक ही है। इन कर्मयोगियों का स्पर्श पाकर कुन्दन बने सहस्रों कार्यकर्ता संगठन की कार्यकर्ता निर्माण की प्रकिया से गुजर कर नेतृत्व का गुण और संगठन कौशल प्राप्त कर आज समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में अपना स्थान बनाने में सफल हुए हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ ही वे कार्यकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों के लिये एक आदर्श रखने में भी सफल हुए हैं।

संगठन के वर्तमान पीढी के कार्यकर्ताओं की क्षमता ही अतीत के कृतकार्यों का प्रतिबिम्ब होती है। आज यदि अभाविप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दावा कर पा रही है तो इस वर्तमान पीढ़ी के बल पर ही, जिसने निरंतरता को बनाए रखा और जो शताब्दी के संकल्प के साथ आने वाले वर्षों के लिये अपने लक्ष्य निर्धारित करेगी।

अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आपका

संपादक

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ध्येय यात्रा

| दत्तात्रेय होसबले |

विश्व के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए हुए जनप्रयासों के इतिहास में विद्यार्थी-युवा आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के संदर्भ में यह बात सत्य है कि 2300 वर्ष पूर्व मगध राज्य में सत्तालोलुप नंद राजाओं के दमन एवं दर्प के विरूद्ध जनता की आवाज उठाने में छात्रों की महती भूमिका रही है और यह सर्वविदित है कि इसके प्रेरक स्वयं आचार्य चाणक्य थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी विद्यार्थी-युवाओं ने असीम पराक्रम, देशभक्ति एवं बलिदान का अद्भुत परिचय दिया। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ आंदोलन हो या 1980 के दशक में असम में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरूद्ध जन-आंदोलन-इन सभी में भारत के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्रों की अग्रणी भूमिका थी।

स्वातंत्र्योतर भारत की छात्र गतिविधियों के इतिहास में अभाविप का एक विशिष्ट स्थान है। वर्तमान समय में विद्यार्थी परिषद अपने उद्देश्य, वैचारिक भूमिका, सिद्धांत, कार्यक्रम व कार्यपद्धति तथा इन सभी से निर्माण होने वाले कार्यकर्ताओं के कारण एक अनोखा एवं अतुलनीय संगठन है। अभाविप आज भारत के अग्रणी एवं अत्यंत शक्तिशाली छात्र संगठन के रूप में जानी जाती है।

अभाविप वर्ष भर सक्रिय रहने वाला देशव्यापी संगठन है। मात्र छात्रों के कुछ मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वाले अथवा समाज या राष्ट्र के सामने आने वाले कुछ प्रश्न-चुनौतियों को लेकर आवाज उठाने तक अपने कार्य को सीमित न करते हुए अभाविप ने एक स्थायी संगठन के रूप में छात्रशक्ति को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य मे सार्थक ढंग से संयोजित करने का एक अनोखा कार्य किया। किसी देश मे छात्र संगठन का उद्देश्य और उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उस दर्शन को विकसित करने का श्रेय विद्यार्थी परिषद

को है। परिषद ने प्रारंभ से ही अपने कार्य के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में एक आदर्श छात्र आंदोलन विकसित करना जो दलगत राजनीति से ऊपर रहकर शिक्षा-परिवार के अस्तित्व में विश्वास रखते हुए छात्रों की सामूहिक शक्ति व ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगाता है।

किसी भी छात्र की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं है – एक छात्र के नाते, दूसरा उसकी नागरिक भूमिका। क्योंकि छात्र, बालक नहीं, अपितु युवा नागरिक हैं जिनकी आंखों में भविष्य के सपने, दिल में सामाजिक संवेदना का वास, स्मृति में अतीत के अनुभव व तन-मन में कुछ करने का ऊर्जा-उत्साह होता है। अतएव सामाजिक संवेदना से युक्त छात्रशक्ति को समाज परिवर्तन के लिए उपयुक्त और पोषक रचनात्मक गतिविधि में सक्रिय करने के कार्य को अभाविप ने महत्व देकर संचालित किया है। शिक्षा-परिसर में वर्ग संघर्ष की बात को ठुकराते हुए शैक्षिक परिवार की अवधारणा को परिषद ने रखा और अपनी कार्यशैली तथा पद्धति से इसे अनुभव में उतारा। यह सब करते हुए शैक्षिक क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तनों के संदर्भ में अपने उत्तरदायित्व की अनदेखी नहीं की, बल्कि उस दिशा में भी सार्थक प्रयास करते हुए एक विशिष्ट अध्याय की रचना की है।

अभाविप ने सैकड़ों प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करने की विशिष्ट प्रतिभा को छात्र समूह में विकसित किया है। विवेकानंद जयंती या प्रतियोगिताएं, बाल संस्कार केन्द्र या निःशुल्क कक्षाएं, रक्तदान या पौधारोपण जैसे सामान्य कार्यक्रमों से लेकर 'ग्राम विकास हेतु छात्र', 'भारत मेरा देश,' 'अंतरराज्ययीय छात्र जीवन दर्शन','विकासार्थ विद्यार्थी' जैसे कई स्थायी एवं प्रभावी प्रकल्पों का आविष्कार कर उन्हें वर्षों तक संचालित करने की परंपरा बनी है। किसी छात्र-संगठन के लिए यह सामान्य बात नहीं थी। इन कार्यक्रमों और प्रकल्पों के माध्यम से ऐसे अनेक युवाओं के व्यक्तित्व का विकास हुआ, जो अपने भावी जीवन में समाजोपयोगी कई रचनात्मक कार्यों में स्वयं लगे और समाज में ऐसे कार्य करनेवाली छोटी, बड़ी टोली तथा संस्थाओं का निर्माण भी किया।

देश की एकता, एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक ताना-बाना, सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में विद्यार्थियों के बीच भावना जागृत करना अनन्य है। इन सबके लिए अनेक आयामों में वर्षों तक लगातार कार्य होते रहे। विद्यार्थियों की पीढ़ी बदलने पर भी मौलिक भावना और विचार में कोई अंतर नहीं आया। कार्य-विस्तार होता गया; प्रभाव बढ़ता गया। परिषद ने इन सारे कार्यों को किसी तात्कालिक लाभ या राजनीतिक दृष्टि से न करते हुए आज के विद्यार्थियों को नागरिक व सामाजिक दायित्वबोध से परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण हेतु अपनी भूमिका निभाने को तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया। यह अभाविप की कोई विवशता नहीं थीं, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का ही परिचायक था। अभाविप ने स्थापना के साथ ही समाज में, विशेषतः विद्यार्थियों के बीच अभिप्राय संग्रह करते हुए देश का नाम भारत हो, संविधान की भाषा हिंदी हो, राष्ट्रगान वंदे मातरम हो– ऐसे एक भारतीयकरण उद्योग का राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह का कार्य अपने कंधों पर लिया जो किसी छात्र संगठन द्वारा किया गया महनीय कार्य है।

अभाविप ने सदैव आग्रह किया कि भारत की सही उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण विचार 'राष्ट्रीय

एकात्मता' और 'भावनात्मक एकता' का है। पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों-युवाओं के बीच जब राष्ट्रविरोधी शक्तियां अलगाववादी विचारों को फैला रही थीं, तब वहां के लोगों को शेष भारत के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास अभाविप ने किया। इसी अभियान के निमित्त अंतरराज्यीय छात्र-जीवन दर्शन (SEIL) उपक्रम की शुरुआत हुई, जिससे 'भारत मेरा घर' जैसा प्रकल्प विकसित हुआ। SEIL प्रकल्प के अंतर्गत विगत अनेक वर्षों से उत्तर-पूर्वांचल राज्यों के हजारों विद्यार्थियों को देश के अन्यान्य भागों को देखने, वहां के जीवनानुभव प्राप्त करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाता है। वर्षों से चल रहे इस प्रकल्प में आए हुए विद्यार्थी जिन परिवारों में दो-चार दिन के लिए रुके, उन परिवारों के लोगों के बीच एक अद्भुत भावनात्मक संबंध बन गया जो जीवनपर्यंत दिलों मे रहा। ऐसे देश के दो भागों को जोड़ने का यह अनोखा प्रकल्प सैकड़ों हजारों परिवारों में पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में सकारात्मक एवं अपनत्व के भाव बढ़ाने में पोषक रहा है।

फाइल फोटो

फाइल फोटो

भारत की एकात्मता का उसकी सुरक्षा जैसा ही महत्व है। जब कश्मीर घाटी में अलगाववादियों-आतंकवादियों ने भारत विरोधी नारे लगा कर वहां के हिंदुओं को अपने ही देश में विस्थापित होने को विवश किया तब आतंकवाद के शिकार बने इन हिंदुओं की रक्षा हेतु अभाविप सामने आई। साथ ही घाटी में उभरे इस भयानक आतंकवाद के विरूद्ध आवाज उठाकर जम्मू-कश्मीर को अलग करने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने की एक राष्ट्रव्यापी मुहिम भी चलायी। 'कश्मीर बचाओ' इस संकल्प के साथ देश के हजारों विद्यार्थियों का समूह निस्वार्थ भाव व असीम राष्ट्रीय प्रेम से ओत-प्रोत हो कर देश की एकता के लिए जम्मू पहुंचना छात्र इतिहास में अनन्य अनुभव था, जो भारतीय इतिहास का एक गौरवास्पद पृष्ठ है।

इसी प्रकार, उत्तर-पूर्वांचल राज्यों, विशेषतः असम में 80 के दशक के प्रारंभ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक संकटों के प्रति असम के साथ-साथ देश के सभी भागों को जागृत करने का कार्य अभाविप ने किया एवं 'आज असम बचाओ ताकि कल देश बचा सके' इस संदेश को गुंजायमान किया। असम छात्र आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ऑल असम स्टूडेंट यूनियन तथा ऑल असम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन को संपूर्ण समर्थन देकर, उस आंदोलन को असम की सीमा से बाहर देशव्यापी बनाने में अभाविप ने ऐतिहासिक भूमिका निभायी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरूद्ध हुए इस आंदोलन में भी विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा जजेज फील्ड में 2 अक्टूबर, 1983 को किया गया सत्याग्रह उस आंदोलन के लिए

मील का पत्थर साबित हुआ। असम के आंदोलन को वैचारिक दर्शन सहित राष्ट्रीयता को समाज से जोड़ने के एक नाजुक पक्ष को विद्यार्थी परिषद ने पहचाना और अपने संपर्क तथा विचार के प्रवाह से उसे सुदृढ़ बना कर कई वर्षों तक देश के विद्यार्थी समूह को इस चुनौती के निवारण की प्रेरणा दी।

1973-74 के गुजरात नव निर्माण आंदोलन को अभाविप ने छात्रशक्ति के रूप में परिचित कराने वाला स्वरूप दिया, जिसकी प्रतिध्वनि बिहार में प्रारंभ हुए छात्र आंदोलन में भी सुनायी पड़ी। परिषद ने उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आंदोलन के नेतृत्व हेतु मनाया। साथ ही स्वयं भी आंदोलन की रीढ़ की हड्डी के रूप में सम्मिलित हुई। जे.पी. आंदोलन नाम से प्रसिद्ध यह राष्ट्रीय संघर्ष आगे जा कर आपातकाल के विरूद्ध हुए संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। आंदोलन की गर्मी को न सहने वाली कांग्रेस का तात्कालिक नेतृत्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में था, जिन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए रातोंरात देश में आपातकाल लाद कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए पूरे देश को एक कारावास के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उस समय जयप्रकाश जी के नेतृत्व वाले आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली अभाविप नागरिक अधिकार, लोकतंत्र व संविधान की रक्षा हेतु, तब तक के अचर्चित रूप वाले इस आंदोलन में सक्रिय हो गयी। भूमिगत आंदोलन करने का अनुभव वर्तमान पीढ़ी को नहीं था, फिर भी, विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य राष्ट्रीय विचार के संगठनों के साथ एक व्यापक संगठनात्मक जाल द्वारा भूमिगत आंदोलन में भी अपना प्रभावी योगदान देकर तानाशाही विरोधी सत्याग्रह में अद्भुत सहभाग का परिचय दिया।

फाइल फोटो

आपातकाल के पश्चात देश के राजनीतिक पटल पर उभर कर आयी जनता पार्टी में विलय होने के निमंत्रण को विद्यार्थी परिषद ने अपने सैद्धांतिक आधार पर राष्ट्रीय दृष्टि को ध्यान में रखकर नकारा तथा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन-संगठनों को सत्ता-राजनीति में लिप्त नहीं होने व स्वतंत्र रूप से सामाजिक प्रतिनिधि के रूप मे अपनी भूमिका निभाने के मूल संकल्प को यथावत बनाए रखा। यह निर्णय आज भी ऐतिहासिक और देशहित की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

आंध्र प्रदेश और वर्तमान तेलंगाना के जंगलों में ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसरों में भी हिंसात्मक मार्ग से समाज में क्रांति लाने के सपने दिखाने वाले नक्सलवादी तत्त्वों के विरूद्ध परिषद कार्यकर्ताओं ने अपना लोहा मनवाया–यह कार्य आसान नहीं था। शस्त्र के बल पर आंदोलन करने वाले संगठनों के विरूद्ध निहत्थे लोगों का संघर्ष- यह जोखिम ही था। तेलुगु राज्यों के विश्वविद्यालय परिसरों को नक्सली तत्वों से मुक्त रखने के इस सकारात्मक प्रयास में अभाविप कार्यकर्ताओं ने अपनी आत्माहुति भी दी। इस संघर्ष में परिषद के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसी प्रकार केरल के शैक्षिक परिसरों में कम्युनिस्टों ने अपनी असहिष्णुता को क्रूर हिंसा के रूप में प्रकट कर परिषद के कार्यकर्ताओं पर बर्बर आक्रमण किए। उन्होंने वैचारिक विरोध को लोकतांत्रिक विधान

व स्वस्थ मन से वैचारिक संघर्ष की जगह विरोधियों का खून बहाने का कार्य किया। ऐसी परिस्थितियों में भी अभाविप कार्यकर्ताओं ने निडर होकर अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को न केवल व्यक्त किया, बल्कि समाज में ऐसे अनैतिक हमलों के विरूद्ध छात्रशक्ति खड़ी हो सकती है—समाज को यह कर दिखाया।

अभाविप ने समाज-परिवर्तन के प्रयासों में सामाजिक समता-समरसता के अत्यंत सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण आयामों को वैचारिक प्रतिबद्धता एवं व्यावहारिक कुशलता से प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपने संगठन को सर्वस्पर्शी बनाने के प्रयास के साथ-साथ समाज-जीवन में समता-समरसता एवं सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करने की दृष्टि से अभाविप ने विभिन्न प्रकार के वैचारिक कार्यक्रमों, रचनात्मक एवं सेवा प्रकल्पों को लगातार संचालित किया है। यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी समूहों में आरक्षण-विरूद्ध हुए बिना, सामाजिक दृष्टि को भंग न होने दिया और सामाजिक समरसता का आग्रह करते हुए समाज को विघटित होने से रोकने के प्रयास किए। मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामांतरण प्रकरण (वर्तमान में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ), बिहार में रणवीर सेना की गतिविधियों के बीच संकल्प-यात्रा करने का निर्णय अथवा स्वातंत्र्यवीर सावरकर की जन्मशताब्दी में उनके क्रांतिकारी जीवन आयाम के साथ-साथ सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य को समाज के सामने लाने का सराहनीय प्रयास विद्यार्थी परिषद की समर्थता व प्रयत्नों का द्योतक है।

देश समाज में महिलाओं की समान सहभागिता के संदर्भ में विद्यार्थी परिषद का आग्रह समाज-परिवर्तन का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। राष्ट्र-पुनर्निर्माण और समाज परिवर्तन के प्रयास में नारी शक्ति को उचित स्थान दिलाने हेतु विद्यार्थी परिषद सतत प्रयत्नशील रही है। अभाविप की पूर्णकालिक छात्राओं की संख्या में वृद्धि, प्रत्येक आंदोलन में छात्राओं की भूमिका को सुनिश्चित करना, छात्र-संघों के संचालन में उनकी भूमिका को महत्व देना या छात्राओं की सुरक्षा हेतु 'मिशन साहसी' जैसे अद्वितीय कार्यक्रमों का संचालन इत्यादि एक छात्र-संगठन के रूप में नारी-शक्ति के प्रति विद्यार्थी परिषद के दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की निकृष्ट राजनीति की पोल खोलने हेतु परिषद ने आंदोलन का नगाड़ा बजाया और इसके पीछे रचे गए कुचक्र की पोल खोली।

फाइल फोटो

छात्रों में नेतृत्व के गुण-विकास हेतु छात्र-संघों के मंच को सुयोग्य एवं सकारात्मक दृष्टि से विकसित करने हेतु विद्यार्थी परिषद सतत प्रयासरत है। छात्रसंघ के चुनाव में दलीय राजनीति, धनबल, बाहुबल या जातिबल का प्रभाव शून्य हो और एक स्वस्थ वातावरण में छात्र-संघों के चुनाव संचालन हेतु विद्यार्थी परिषद ने समय-समय पर अपने विचार समाज के सम्मुख रखे, विद्यार्थियों का मन तैयार किया व प्रशासन को सही मार्ग पर चलने को विवश किया।

यद्यपि विद्यार्थी परिषद भारत के अंदर राष्ट्र-निर्माण हेतु कार्य करने वाला संगठन है तथापि पड़ोसी देश

में चलने वाली गतिविधियों के संदर्भ में वह न तो अनभिज्ञ रह सकता है और न ही अनुत्साहित। यही कारण है कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं के कारण भारत पर होने वाले प्रभाव का विद्यार्थी परिषद ने अध्ययन व आकलन किया। अतः समय-समय पर उन विषयों के बारे में विचार-गोष्ठी का आयोजन करना या अपने विचार प्रकट करने हेतु प्रस्ताव या वक्तव्य जारी करना आदि विद्यार्थी परिषद ने अपने कार्य का हिस्सा माना है।

विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के छात्र अध्ययनरत रहते हैं, जबकि छात्र-आंदोलन सामान्यतः देश की सीमा तक अपने कार्यक्षेत्र को निश्चित करताहै; परंतु दृष्टि व भावविश्व के कारण वैश्विक छात्र-युवा गतिविधियों से परिचित होना, उसके प्रति संवेदनशील रहना सहज धर्म है। इसी कारण विद्यार्थी परिषद ने 'भारत विदेशी छात्र मंडल' जैसे सांस्कृतिक मंचों की स्थापना कर परस्पर सांस्कृतिक परिचय, स्नेह व सहयोग के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया; उसी दिशा में आगे बढ़कर 'अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष 1985' में 'विश्व विद्यार्थी युवा संघ' (WOSY) नामक एक छात्र-युवा संगठन को जन्म देने का ऐतिहासिक कार्य अभाविप की जीवन यात्रा में संपन्न हुआ। आज यह संगठन एक प्रभावी मंच के रूप में विकसित हुआ है। इसमें कार्यरत अनेक देशों के छात्र 'सारा विश्व एक है' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की दृष्टि को अपनी अनुभूति में समाए हुए हैं।

इन सभी कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थी परिषद अपने संगठनात्मक कार्य-विस्तार के प्रति सदैव सजग और प्रयत्नशील रहा। यही कारण है कि पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से त्रिपुरा तक, देश में दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक या उत्तर में हिमाच्छादित लद्दाख तक विद्यार्थी परिषद की इकाइयों का कार्य चलता है और इन स्थानों से भी संगठन का काम करने हेतु पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकलते हैं।

प्रारंभ में असम व अन्य उत्तर-पूर्व राज्यों में कार्य-विस्तार हेतु परिषद ने अन्यान्य राज्यों से अपना पूर्ण समय देने वाले कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। इन संगठनात्मक प्रयत्नों से न केवल कार्य विस्तार हुआ अपितु 'हम सब एक देश के नागरिक हैं'—राष्ट्रीय एकात्मता का यह भाव भी सुदृढ़ होता गया।

अभाविप ने कार्यकर्ता-निर्माण एवं विकास हेतु प्रशिक्षण वर्गों को प्रयत्न-पूर्वक शास्त्रीय विधान से विकसित किया। विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से होने वाले इन अभ्यास वर्गों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद की हर पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता, कार्यक्रम संचालन-विधि का परिचय, कार्यपद्धित हेतु प्रतिबद्धता, एक नागरिक के नाते दायित्व-बोध एवं संगठनात्मक गुणों से ओत-प्रोत होने का अवसर मिलता है, जिसे हर कार्यकर्ता जीवन भर स्मरण रखने के साथ उससे प्राप्त प्रकाश में यथासंभव आगे बढ़ने का प्रयास करता है।

अभाविप के प्रशिक्षण वर्ग एवं कार्यक्रमों के द्वारा मात्र छात्र संगठन के सिपाही ही तैयार नहीं होते, बल्कि भारत के एक राष्ट्रनिष्ठ, सामाजिक दायित्वबोध युक्त, रचनात्मक दृष्टि-संपन्न नागरिक भी निर्मित होते हैं। परिषद के अखिल भारतीय अधिवेशनों में सहभागी कार्यकर्ता केवल सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता की अनुभूति से अपने-अपने स्थान पर कुछ करने की प्रेरणा लेकर जाते हैं। 'शिक्षा जीवन के लिए : जीवन वतन के लिए'— विद्यार्थी परिषद का यह मंत्र इन्हीं आयोजनों के कारण साकार होता है।

अभाविप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रनिष्ठ आंदोलन से प्रेरणा लेकर कार्य कर रही है, अतः स्वाभाविक ही वह राष्ट्रीय विचार से अनुप्राणित होकर राष्ट्रीय उद्देश्य हेतु अपना जीवन लगाने वाला छात्र-संगठन बना है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में सामाजिक संगठनों के योगदान के संदर्भ में विद्यार्थी परिषद के कार्यों का स्थान अनुपम है। उसने 'राष्ट्र सर्वोपरि' की भावना से अपने जीवनव्रत को निभाया है और इस मार्ग पर आगे चलने का उसका पवित्र संकल्प भी है। राष्ट्रीय अभियान का यह इतिहास राष्ट्रधर्म के पुनीत विचार-तरंग का उद्भव कर, हमें जीवनपर्यंत उस दिशा में सक्रिय होने की प्रेरणा दे सके, यही आशा और विश्वास है। ■

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मा. सरकार्यवाह हैं, पूर्व में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं।)

मेरी पहचान के निर्माण में अभाविप का महनीय योगदान : राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया

गुवाहाटी में अभाविप के अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) अपनी स्थापना के 75 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 75 वर्ष होने के अवसर पर अभाविप देशभर में अमृत महोत्सव समारोह करने की व्यापक तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में गुवाहाटी में अभाविप के अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह गुवाहाटी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र अंतराष्ट्रीय सभागार में हुआ। समारोह में हजारों की संख्या में अभाविप के प्रांत भर के वर्तमान कार्यकर्ता, पूर्व-कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के शुभचिंतक, समाज के विशिष्ट लोग, असम के विभिन्न विश्वविद्यालों के कुलपति एवं शिक्षा क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मेरे व्यक्तित्व और पहचान के निर्माण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महनीय योगदान है। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो विद्यार्थी परिषद के कारण ही पहुंचा हूं। मैं भी आप सब की ही तरह इस यात्रा का यात्री रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी ने सबसे ज्यादा बलिदान किया है। युवा शक्ति ने इतिहास में मुगलों के शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। विदेश में पढ़ने के लिए गए क्रांतिकारियों ने वहां भी मशाल जलाई। देश हित में आजादी के बाद पहला संगठन अभाविप बना।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद की पीढ़ी ने असम को बचाने के लिए कार्य किया। सील यात्रा के माध्यम से देश को एकात्मता के डोर में बांधने का कार्य लगातार जारी है। राजस्थान के गोबिंद गुरु को स्थापित करने में भी परिषद का महत्वपूर्ण योगदान है। युवाओं के बल पर ही 2047 तक भारत विश्वगुरू बनेगा, जिसमें विद्यार्थी परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

असम के साथ विद्यार्थी परिषद का पुराना नाता: सुनील आंबेकर

अमृत महोत्सव उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख तथा अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि जब छात्रों को हिंसा सिखाई जाती थी, उस समय विद्यार्थी परिषद ने देश के लिए जीने का संदेश दिया। देशहित, समाज हित का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि असम के साथ विद्यार्थी परिषद का पुराना नाता है। राज्य में जब छात्रों को हथियार दिया जा रहा था, उस समय विद्यार्थी परिषद ने युवाओं में लोकतांत्रिक चेतना की अलख जगाई। परिषद ने असम की समस्या को देश से अवगत कराया और इस आंदोलन को देशव्यापी बनाया। अपने उदबोधन में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत माता की जय बोलने का मतलब देश में शांति के प्रति आस्था, देश के विकास के लिए आकांक्षा और देश के उज्ज्वल भविष्य की चाह रखने वाली इच्छा की जय है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी परिषद देशभक्ति की मशाल को आगे लेकर जाएगा।

इस अवसर पर अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि असम को बचाने में विद्यार्थी परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभाविप ने अपने स्थापना से ही राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा, यही कारण है परिषद से निकले कार्यकर्ता आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं। अभाविप असम के प्रांत संगठन मंत्री अनूप कुमार ने बताया कि परिषद ध्येय यात्रा के 75 वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुवाहाटी में गत 18 जून को संपन्न अभाविप अमृत महोत्सव के उदघाटन समारोह में अभाविप असम प्रांत अध्यक्ष रोबिन काकोटी, प्रदेश मंत्री सीमांत कु वैश्य, राष्ट्रीय मंत्री राकेश दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

शिक्षा की प्रक्रिया से न तो कोई छात्र छूटे और न ही कोई टूटे : राजशरण शाही

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। अब तक की यात्रा के दौरान अभाविप ने राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया और सपूर्ण विश्व में सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अभाविप के 74 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका ने अभाविप अध्यक्ष राजशरण शाही से कई अहम विषयों पर वार्ता की। वार्ता के दौरान अभाविप अध्यक्ष शाही ने कहा कि जब छात्र संगठनों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि अधिकांश छात्र संगठन किसी घटना या परिस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं और उस घटना या परिस्थिति के समाप्त होते ही उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में भी अभाविप उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि यह एक विचार की यात्रा है। इसीलिए हमने इस यात्रा को ध्येय यात्रा कहा है। इस ध्येय यात्रा ने केवल शैक्षिक परिवर्तनों को ही रचनात्मक दिशा नहीं दिया है, बल्कि छात्रों के बारे में समाज की धारणा को भी बदला है। अतः इसे मैं केवल एक छात्र संगठन की यात्रा के रूप में नहीं, बल्कि छात्र संगठन के दर्शन के रूप में देखता हूं।

शैक्षिक परिवर्तनों में अभाविप की भूमिका के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि शिक्षा के विषय में बहुत ही स्पष्ट मत है। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में गहराई से जुडी हो तथा उसकी प्रतिबद्धता विकास के प्रति हो। पश्चिम की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत में शिक्षा तंत्र विकसित करने के स्थान पर भारतीय मूल्यों, परंपराओं तथा आकांक्षाओं के आधार पर शिक्षा का तंत्र खड़ा हो, इसके लिए अभाविप स्वतंत्रता के पश्चात लगातार प्रयास करती आ रही है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम के रूप में राष्ट्रीय

शिक्षा नीति-2020 आई है। इस नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा तथा भारतीय भाषाओं के आधार पर शिक्षा की रचना खड़ा करने का संकल्प व्यक्त किया गया है, जिसे भारत केन्द्रित शिक्षा की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा के रूप में खड़ा करने तथा स्वावलंबी भारत के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से यह शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों की रुचियों, क्षमताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा का तंत्र खड़ा करने का प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। इसमें भारत बोध का भाव तथा छात्र केंद्रित शिक्षा का प्रभाव दोनों दिखाई देता है।

नयी शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में अभाविप अध्यक्ष शाही ने कहा कि भारत को यदि विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो ज्ञान के साथ ही साथ अनुसंधान पर विशेष ध्यान

देना ही होगा। अनुसंधान की मात्रा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाना, भारतीय शिक्षा के सामने बड़ी चुनौती है। भारत के शोधार्थियों को अनुसंधान की वैश्विक सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही उनकी प्रतिभा को नई उड़ान दे सकते हैं। आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को विश्व स्वीकार ही नहीं कर रहा, बल्कि उसे यथोचित सम्मान भी दे रहा है। वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु विश्व की दृष्टि भारत के युवाओं की ओर है। भारत की ज्ञान परंपरा तथा पद्धतियों के प्रति विश्व का आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में विदेशी को स्वदेशानुकूल तथा स्वदेशी को युगानुकूल बनाने की दृष्टि से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह देश के छात्रों को भारत की भाषाओं में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसी अपेक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अभाविप की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि अभाविप के अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों पर अगर दृष्टि डाली जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति अभाविप कितनी सचेष्ट और जागरूक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप इसका क्रियान्वयन हो, इस हेतु प्रांत स्तर पर समिति के गठन के साथ-साथ कार्यशालाओं के आयोजन तथा शिक्षाविदों, कुलपतियों, प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्रों व समाज के साथ लगातार संवाद के माध्यम से अभाविप अपनी प्रभावी भूमिका हेतु प्रयत्नशील है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमृत काल में प्रवेश कर रही है, ऐसे में आगामी दिशा क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में अभाविप अध्यक्ष शाही ने कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से अभाविप की स्थापना हुई है। इस संकल्प की सिद्धि हेतु प्रत्येक विद्यार्थी तक अभाविप की पहुंच हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षालय दबाव और तनाव उत्पन्न करने के बजाए आनंद के केंद्र बने, शिक्षा की सार्थकता उत्तर बढ़े, प्रत्येक छात्र को उसकी प्रकृति एवं संस्कृति के अनुरूप विकसित करने की योजना हो, इस दिशा में आने वाले दिनों कार्य किया जाएगा। अभाविप का प्रयास रहेगा कि शिक्षा की ऐसी रचना खड़ी की जाए, जिससे शिक्षा की प्रक्रिया से न तो कोई छात्र छूटे और न ही कोई टूटे। ■

विज्ञान अध्येतावृत्तियों में बढ़ोत्तरी का अभाविप ने स्वागत किया

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने केंद्र सरकार द्वारा शोध व विकास गतिविधियों में संलग्न कनिष्ठ/वरिष्ठ शोध अध्येताओं व रिसर्च एसोसिएट की अध्येतावृत्ति में बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधी निर्णय का स्वागत किया है। अभाविप ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि समयानुसार अध्येतावृत्तियों में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

अभाविप ने केंद्र सरकार से यह मांग भी की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित अन्य संस्थाओं की अध्येतावृत्तियों तथा शोध प्रोजेक्टों के लिए निर्धारित राशि में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए, जिससे वर्तमान में शोध के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए शोधार्थी गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य कर सकें।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के अनुसार देश में शोध व नवाचार क्षेत्र में शीघ्रता से प्रगति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। अभाविप सरकार से मांग करती है कि देश के शोध ढांचे को विश्वस्तरीय करने निमित्त आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शोधकर्ताओं से नियमित संवाद द्वारा विभिन्न अवरोधों को दूर कर स्वस्थ, रचनात्मक व गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। ■

UNIFORM CIVIL CODE – A STEP TOWARDS HARMONY AND SOCIAL COHESION

| Pankaj |

The Uniform Civil Code has been in the news in recent times due to discussions and debates on the subject, being a big and important issue. UCC stands for the Uniform Civil Code. It is a proposed set of laws aimed at governing matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption for all citizens of India, regardless of their religion. The idea behind the Uniform Civil Code is to have a common set of laws that wouldpromote gender equality, individual rights, and social justice by eliminating discriminatory practices present in certain personal laws. It is believed that a common set of laws would help create a more unified and cohesive society, transcending religious divides. To understand more on the issue, we have delved upon the legal framework in India governing the issues mentioned above and provided the views of apex court on the same. Some benefits have also been highlighted below to gain more insight on the Uniform Civil Code, hereinafter called UCC.

Divorce – Maintenance – Guardianship & Adoption Laws

Some political parties allege that the government wants to abolish personal laws on the pretext of Uniform Civil Code. These parties, citing Article 25 of the Constitution, say that everyone is free to follow their own religion. But it is necessary to mention here that Article 25 is not an absolute right. Article 25 gives qualified freedom to citizens subject to public order, health and morality. Further, this article is subject to other rights mentioned under Part 3 of the Constitution of India. In which the right to equality comes prominently i.e. Article 14 of COI. Women and men should get equal rights. Whether it is about rules relating to marriage, divorce, succession, inheritance, guardianship or adoption. These subjects appear to be lop sided in Islam, which are completely dependent on the Alim and Qazi in their community today. In the Muslim community, women have the right to divorce only through Qazi, while men can directly give divorce. Even after criminalizing talaq-e-biddat, the man in Islam has the right to claim talak like talaq-e-hasan, talaq-e-ehsan, talaq-e-Ashan, and talaq-e-Ila which are still happening today through sms, whatsapp, telegram, courier and email.

Guardianship remains completely with the male member of society in Islam, there is an urgent need for change in it with progressive thinking.Adoption is considered prohibited in Islam.After the UCC it will not be possible to take away the rights of women under the guise of personal laws.

Supreme Court views:

The demand for Uniform Civil Code in India is not from today but since many decades. If we see, constituent assembly debates, we notice that while making the constitution, the framers of the constitution have also talked about bringing it under article 44 of the constitution. Even the responsibility factor had been attached to State for its implementation in terms of creating a conducive environment for it. Today, after 74 years, we see that more than 12 High Courts and Supreme Court have observed

that Uniform Civil Code is desirable as a law to prevent social fabric of society. Many a times the Supreme Court has highlighted in its judgments the evils spreading in the society due to its non-implementation. In the case of Sarla Mudgal, the Supreme Court observed,

"We, therefore, request the Government of India through the Prime Minister of the country to have a fresh look at Article 44 of the Constitution of India and endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

We further direct the Government of India through Secretary, Ministry of Law and Justice to file an affidavit of a responsible officer in this Court in August, 1996 indicating therein the steps taken and efforts made, by the Government of India, towards securing a "uniform civil code" for the citizens of India.."

Benefits of embracing Uniform Civil Code:

Uniform Civil Code will strengthen the social fabric. Along with this, it will also be helpful in fighting economic, religious and social discrimination. It will also promote gender equality. Under uniform structure of civil laws in India, complex laws will be simplified and gender bias will end. Following are certain advantages which necessitates the implementation of common civil code at the earliest.

1. Harmonization of Laws and UCC

India, as a diverse and multicultural nation, is governed by a unique legal framework that recognizes personal laws based on religion, leading to variations in matters of marriage, divorce, inheritance, and other personal affairs. However, the absence of a Uniform Civil Code (UCC) has generated debates and discussions over the years. This article aims to delve into the concept of UCC and present arguments in Favor of its implementation in India. By analysing the potential benefits of a UCC, including promoting equality, secularism, and social cohesion, it becomes evident that the time has come for India to embark on the path of a unified legal system.

2. Promoting Gender Equality:

One of the key arguments in favour of a UCC is its potential to advance gender equality. India has made significant strides in empowering women, but the existence of diverse personal laws often leads to disparities in rights and opportunities. A UCC would ensure that women, regardless of their religious background, have equal rights in the affair of marriage, divorce, inheritance, and maintenance laws. By providing a level playing field, a UCC would alleviate discriminatory practices prevalent in some personal laws, empowering women and reinforcing their rights as equal citizens.

3. Religious Neutrality:

Implementing a UCC would promote religious neutrality by establishing a common set of laws applicable to all citizens, regardless of their faith. This uniformity would foster a sense of unity and ensure that the state does not favor or endorse any particular religious community over others.

4. Simplification of Laws:

The coexistence of multiple personal laws in India often creates legal complexity and confusion. A UCC would harmonize and streamline the legal framework, replacing various laws with a single code. This simplification would not only reduce legal disputes but also enhance access to justice for all citizens. Moreover, a UCC would eliminate the need for individuals to navigate through different legal systems, reducing administrative burden and promoting efficiency in legal processes.

5. Promoting Social Cohesion:

A UCC has the potential to foster social cohesion by promoting a sense of unity among diverse communities. India's strength lies in its diversity, and a UCC would serve

as a unifying force by transcending religious boundaries and reinforcing the idea of a common national identity. It would encourage interfaith relationships and create a shared understanding of rights and responsibilities. By promoting social cohesion, a UCC would contribute to the overall stability and progress of the nation.

In Nutshell:

Uniform Civil Code is neither a communal issue nor an issue of any party's manifesto. It is an ideological issue of the society; it is a women's rights issue. Uniform Civil Code is such an inclusive law that empowers the whole society in India. To say that, Personal law is the constitution, we have to come out of this thinking and we have to fulfill our responsibility by being a partner and contributor in the development of the society. The implementation of a Uniform Civil Code in India has long been a topic of debate, with arguments both in favor and against. However, considering the imperatives of gender equality, social cohesion, and harmonization of laws and religious neutrality, it becomes evident that a UCC is necessary to foster a more egalitarian society. By ensuring equal rights and opportunities for all citizens, regardless of their religious background, a UCC would not only promote justice but also strengthen the social fabric of the nation. As India moves forward, it is crucial to embrace the principles of equality, secularism, and unity by adopting a Uniform Civil Code that reflects the aspirations of a modern and progressive society. ■

खेल गतिविधि आयाम द्वारा महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन, रानी लक्ष्मीबाई टीम विजयी घोषित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दिल्ली प्रांत के खेल गतिविधि आयाम ने गत 28 जून को मालवीय नगर स्थित पुष्प विहार (सेक्टर-1) में छात्राओं के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्पर्धा में कुल 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मैच रानी लक्ष्मीबाई टीम एवं भगिनी निवेदिता टीम के बीच हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई टीम विजयी घोषित हुई।

प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि एवं अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री राम कुमार एवं प्रांत नगरीय कार्य प्रमुख डा. रेखपाल सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रांत के खेल आयाम प्रमुख डा. सुशील ने टॉस कर खेल का विधिवत प्रारंभ किया। विजयी टीम को प्रमाणपत्र एवं पारितोषिक प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रांत खेल संयोजक शुभांकर ने कहा कि अभाविप आने वाले समय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही विभिन्न बस्तियों में योग

प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी, जिससे स्वस्थ जीवन-सुखी जीवन के मंत्र के साथ आम जनमानस को जागरूक किया जा सकेगा। कार्यक्रम के अन्त में प्रांत खेल सह-संयोजिका जोशना सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। ■

अभाविप कार्यकर्ताओं पर केरल पुलिस का बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल

अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण के मामले में जांच की मांग कर रही है अभाविप

केरल स्थित कोच्चि में अवैध रूप से अंग व्यापार के मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी क़ानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। पुलिस की उग्र कार्रवाई में दस से अधिक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शन कर रहे अभाविप केरल प्रांत के मंत्री एन.सी.टी. हरि, प्रदेश सह मंत्री एस. अरविंद सहित दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए अभाविप मंत्री एन.सी.टी. श्रीहरि ने बताया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन के माध्यम से परिषद यह मांग कर रही थी कि अस्पताल में मस्तिष्क संबंधी समस्या के कारण हुई कथित मौतों एवं अवैध ढंग से अंग प्रत्यारोपण मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राज्य की निरकुंश वामपंथी सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और सरकार के इशारे पर पुलिस ने अभाविप कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज में कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए। गत 17 जून को कोच्चि में हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद उन्होंने घोषणा की है कि पुलिस की मार से परिषद कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भविष्य में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, तब तक परिषद अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखेगी।

जानकारी हो कि कोच्चि स्थित वीपीएस लेकशोर अस्पताल में 29 नवंबर 2009 को मोटर साइकिल दुर्घटना में घायल हुए एक युवक एबिन को डॉक्टरों ने कथित रूप से ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। बाद में डॉक्टरों ने एबिन के रिश्तेदारों से उसके प्रमुख आंतरिक अंगों को दान करने के लिए कहा। एबिन की मां ने अनुरोध को यह सोच कर स्वीकार कर लिया था कि इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एबिन के अंगों का अवैध ढंग से प्रत्यारोपण एक मलेशियाई नागरिक के शरीर में कर दिया गया। बाद में इस मामले का सच सामने

आया। लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के बाद 2020 में मामला न्यायालय पहुंच गया। न्यायालय में मामले की जांच की मांग के लिए याचिका कोल्लम निवासी डॉक्टर एस. गणपति ने दाखिल की थी। न्यायालय ने अब अस्पताल और आठ डॉक्टरों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिए हैं। इन सभी पर आरोप है कि एविन का लिवर एक मलेशियाई मूल के व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया और दस्तावेजों में उसकी पत्नी को डोनर बताया गया। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)*

गीता प्रेस को मिले शांति पुरस्कार के विरोध में उतरे छद्म हिंदूवादी

| संजय दीक्षित |

भारत में दशकों से सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार करने वाले गीता प्रेस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर से संचालित गीता प्रेस को शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा सार्वजनिक होने के बाद सम्पूर्ण विश्व में रहने वाले सनातन हिन्दू धर्म के अनुयायियों ने उत्साह के साथ निर्णय का स्वागत किया। लेकिन केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस और वामपंथी दल एकजुट होकर मैदान में उतर गए और उन्होंने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया है।

जानकारी हो कि गीता प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी ढंग से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान और सनातन हिन्दू धर्म-संस्कृति के प्रचार-प्रसार की दिशा में किए जा रहे योगदान के लिए दिया जाएगा। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी, लेकिन इससे पहले ही पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता में प्रेस की नींव रखी जा चुकी थी। गोरखपुर में एक किराए के मकान में स्वर्गीय जयदयाल गोयनका, घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने एक साथ मिलकर गीता प्रेस की शुरुआत की थी। 1926 में गीता प्रेस ने उस किराए वाले मकान को खरीद लिया। विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस के माध्यम से सनातन हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार के प्रणेता स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। स्वर्गीय पोद्दार (1892-1971) स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रहने वाले देशप्रेमी, साहित्यकार और आध्यात्मिक पत्रिका, कल्याण के संस्थापक संपादक थे।

स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत के सनातन हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू संस्कृति और सनातन हिन्दू समाज के विरुद्ध विदेशी मुस्लिम आक्रांता और ब्रिटिश सत्ता के साथ आई ईसाई मिशनरियां अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय थी। सभी का लक्ष्य येन-केन-प्रकारेण सनातन हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट करना था। मुस्लिम और ईसाई मिशनरियों द्वारा कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन और सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध होने

वाले कार्यों ने स्वर्गीय पोद्दार को अहसास कराया कि भारत के मूल सनातन समाज को अपने धर्म, संस्कृति और मूल्य प्रणाली पर गर्व पैदा होना चाहिए और इसके लिए गंभीरता से कार्य करना होगा। उधर स्वर्गीय पोद्दार के विचारों से भयभीत होकर ब्रिटिश सत्ता ने गिरफ्तार करके उन्हें कई माह तक जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में उनका झुकाव राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ता चला गया।

जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म के पवित्र एवं पूज्य ग्रन्थ रामायण और महाभारत के नायकों के गौरव और वीरतापूर्ण कार्यों को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाने के लिए 1927 में 'कल्याण' मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया, जो पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशों में रहने वाले सनातन हिन्दू लोगों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली पत्रिका बन गयी। उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण और उपनिषद जैसे पवित्र सनातन हिन्दू ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कर आम लोगों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सनातन हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार के उनके अथक प्रयासों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता हैं। गीता प्रेस का मुख्य उद्देश्य सनातन हिन्दू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथों गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, प्रख्यात संतों के प्रवचन और अन्य चरित्र-निर्माण पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करके आम जनता के बीच सनातन हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और फैलाना है।

गीता प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय जयदयालजी गोयंदका एक निष्ठावान भक्त और उत्कृष्ट आत्मा थे। उन्होंने मानव जाति की दुर्दशा के लिए रामबाण के रूप में गीता को बहुत महत्व दिया और सभी के बीच अच्छे इरादे और अच्छे विचार फैलाने के लिए इसे और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों का प्रकाशन प्रारम्भ किया। जानकर आश्चर्य होगा कि गीता प्रेस में प्रत्येक दिन का प्रारम्भ सुबह की प्रार्थना से होती है। संस्था में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को भगवान का नाम कई बार याद दिलाने के लिए एक व्यक्ति दिन भर संस्था के अंदर घूमता रहता है। वर्तमान में गीता प्रेस विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है और अब तक गीता प्रेस 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है, जिनमें श्रीमद्भगवद्गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं।

प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस को सम्मानित किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रेस के प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी ने पुरस्कार के साथ मिलने वाली एक करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करना हमारा सिद्धांत है। इसलिए प्रेस के न्यास बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम पुरस्कार के साथ मिलने वाली धनराशि नहीं लेंगे।

लेकिन गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने के बाद कांग्रेस, वामपंथी और अन्य सनातन हिन्दू धर्म विरोधी तत्व जिस तरह विरोध करते हुए एकजुट होकर सामने आए हैं, उससे उन सभी की असलियत भी सामने आ गयी है। ऐसे छद्म हिंदूवादियों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' जुलाई 2023 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

अमर बलिदानी सिदो-कान्हू की याद में अभाविप (झारखण्ड) ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम

हूल दिवस (30 जून) के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा झारखंड प्रांत के अनेक भागों में माल्यार्पण, संगोष्ठी, खेल-कूद, समान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इकाई दर्शन जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित कर हूल क्रांति के नायक वीर सिदो-कान्हू को याद किया। रांची स्थित सिदो-कान्हू पार्क में लगी उनकी प्रतिमा पर अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल सहित अन्य अभाविप कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए गौरव का दिन है। यह एक ऐसी क्रांति है, जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पचास हज़ार योद्धाओं ने सशस्त्र विद्रोह किया था। इसी को हूल क्रांति कहा जाता है। 30 जून 1855 को स्वराज, स्वशासन और स्वधर्म के संकल्प के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र विद्रोह में हुई लड़ाई वर्तमान झारखंड के साहिबगंज के भोगनाडीह में लड़ी गई थी। नेतृत्वकर्ता महान योद्धा सिदो-कान्हू ने अपने भाई चांद-भैरव और बहन फूलों-झानों के साथ सर्व समाज को एकत्रित कर स्वाधीनता के आंदोलन का सूत्रपात किया। विदेशी धर्म को मानने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध यह सबसे भीषण विद्रोह और दूसरी सशस्त्र क्रांति थी। ब्रिटिश शासन की पराजय की पटकथा यही से आरंभ हुई।

उन्होंने कहा कि सिद्दू-कान्हू के नेतृत्व में पुरुष क्रांतिवीर स्वराज के लिए संकल्पित थे, वही महिलाओं की सशस्त्र और सशक्त वाहिनी का नेतृत्व फूलों-झानों ने सम्भाल रखा था। दुर्भाग्य से वामपंथी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता के इस आंदोलन को, जो 1857 से दो वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था, उचित सम्मान नहीं दिया। जनजातीय योद्धाओं के इतिहास से देश को अनभिज्ञ रखने का षड्यंत्र माओ-लेनिन वादियों ने किया है।

हूल दिवस के अवसर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में अभाविप द्वारा संगोष्ठी का आयोजन कर उनके अमर बलिदानी गाथा से वर्तमान पीढ़ी को परिचित करवाया गया। वक्ताओं ने वीर सिदो-कान्हू के जीवन चरित्र से परिचित कराते हुए कहा कि 1855 की हूल क्रांति 1857 के स्वातंत्र्य समर की पूर्व पीठिका थी।

सिदो-कान्हू के एक आह्वान पर गांव के गांव उमड़ पड़ते थे। आज के युवाओं की उनके जीवन से सीख लेकर राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

साहेबगंज में सिदो-कान्हू पर आधारित समान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देवघर के विभिन्न छात्रावासों में हूल दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने अपने पारंपरिक जनजातीय वस्त्रों में प्रस्तुति दी एवं सिदो-कान्हू के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अभाविप चाईबासा

इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा डीपीएस विद्यालय में अमर नायक सिदो-कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया एवं संगोष्ठी का आयोजन किया।

धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यह आन्दोलन 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन की पूर्व की पृष्ठभूमि थी। यह सबसे अधिक संगठित और सशक्त आन्दोलन था, जो संथाली अपनी माटी व मातृभूमि के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गए। एक छोटे से गांव से हूल से शुरू हुआ आंदोलन पूरे संथाल में फैल गया, जो हूल दिवस के नाम से जाना जाता है। झारखंड वासियों को उन महान सपूतों के त्याग, संघर्ष, बलिदान व उत्सर्ग से प्रेरणा लेकर झारखंड राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मेहरमा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप प्रदेश सह मंत्री सौरभ झा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज की अग्रणी भूमिका रही है। अभाविप झारखंड द्वारा हूल दिवस पर जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, रामगढ़, हजारीबाग, चाईबासा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, खूंटी सहित अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने शोभायात्रा, माल्यार्पण, विचार संगोष्ठी एवं समान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर सिदो-कान्हू को याद किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

जम्मू-कश्मीर

अभाविप द्वारा आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम में छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा जम्मू-कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर मिशन साहसी के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। अभाविप स्कास्ट की जम्मू ईकाई ने जून के दूसरे सप्ताह में छात्राओं के लिए चार दिवसीय आत्मरक्षा कार्यक्रम मिशन साहसी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्राओं को आवश्यक आत्मरक्षा कौशल के साथ सशक्त करना था। कार्यक्रम के अंतिम दिन स्कास्ट-जम्मू के प्रभारी कुलपति डॉ. एस. के. गुप्ता ने भाग लेने वाली छात्राओं के साथ बातचीत की।

अभाविप डोडा इकाई द्वारा चलाए जा रहे मिशन साहसी का "मेगा प्रदर्शन" हुआ, जिसमे पांच विद्यालयों की 500 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। अभाविप ने जून के प्रथम एवं दूसरे सप्ताह में मिशन साहसी के तहत नगर के स्कूलों की 1200 छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं ने स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

अभाविप जम्मू विश्वविद्यालय इकाई ने भी जून के प्रथम सप्ताह में चार दिनों तक मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन दिवस पर मेगा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को प्रदर्शित किया जो उन्होंने सीखे थे। इस अवसर पर मुख्य अथिति प्रोफेसर नीलू रोहमेत्रा एवं सम्मानित अथिति के रूप में जम्मू-कश्मीर अभाविप मंत्री अक्षी बिल्लोरिया भी उपस्थित रही। कार्यक्रम का प्रारम्भ विदुषी द्वारा गाए गए परिषद गीत से हुआ। मिशन साहसी कार्यक्रम की संयोजक अनन्या राठौड़ ने मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत की गई गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अथिति प्रोफेसर नीलू रोहमेत्रा ने कहा कि लड़कियों को आत्म-रक्षक, आत्मविश्वासी, सशक्त और निडर बनाना समय की मांग है। अगर एक महिला साहसी और साहसी बन जाती है, तो कई लड़कियां उसके जैसा बनने के लिए उसका अनुसरण करती हैं और समाज में उनका सम्मान और स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने मिशन साहसी कार्यक्रम को उत्कृष्ट रूप से सफल बनाने के लिए जेयू अभाविप इकाई के सभी कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से छात्राओं को बधाई दी। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)* ■

बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाने पर कई राज्य सहमत

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा में तेजी से सुधार प्रक्रिया में लगा हुआ हैं। सुधार की जारी प्रक्रिया के अंतर्गत अब विभिन्न राज्यों में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में एकरूपता होने से छात्रों के बीच की असमानता की खाईं को दूर करने के साथ ही छात्र-छात्राओं को होने वाली असुविधाओं को दूर किया जा सकेगा।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की पहल पर कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षा में एकरूपता लाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। सहमत होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, नगालैंड, ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि शामिल है। अन्य राज्यों ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है, लेकिन अपनी सहमति देने के लिए उन्होंने और समय मांगा है। राज्यों के साथ ही मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाने का दायित्व केंद्रीय मूल्यांकन नियामक 'परख' को सौंपा गया है। नियामक राज्यों को अपने आवश्यक सुझाव दे रहा है।

शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाने की पहल तब की है, जब शिक्षा सुधार अभियान में शिक्षा बोर्डों में भारी असमानताओं की जानकारी सामने आई। वर्तमान में देश के अंदर लगभग 60 स्कूली शिक्षा बोर्ड हैं और यह सभी अपने-अपने ढंग से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी राज्यों से अपने छात्रों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, इसकी आवश्यकता बताई है। मंत्रालय के प्रयासों से अधिकतर राज्यों को इसकी आवश्यकता समझ में आ भी गई है। हाल ही में पुणे (महाराष्ट्र) में राज्यों के शिक्षा सचिवों की बैठक में कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाने का समर्थन किया। प्रस्ताव पर सहमति देने वाले कई राज्य आगामी परीक्षाओं से इस सुधार को लागू करने के पक्ष में भी हैं। साथ ही राज्यों ने परख से इस विषय पर आवश्यक जानकारी मांगी है।

बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता होने के बाद भविष्य में एक राज्य से दूसरे राज्यों में छात्रों के अंकों बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। वर्तमान में स्थिति यह है कि दसवीं में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 63 प्रतिशत से अधिक छात्र 80 प्रतिशत अंक हासिल करके पास होते हैं, तो असम और पंजाब में 80 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्रों का प्रतिशत केवल 19 प्रतिशत के लगभग ही रहता है। ऐसी ही स्थिति बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में भी देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के 58 प्रतिशत छात्र 80 प्रतिशत अंक के साथ परीक्षा को पास करते हैं, जबकि ओडिशा, हरियाणा में 80 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों की संख्या केवल 23 प्रतिशत के लगभग ही रहती है। शिक्षा बोर्ड के मध्य ऐसी असमानताओं का कुप्रभाव छात्रों के एक राज्य से दूसरे राज्यों में स्थान्तरित होने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और छात्रों का प्रदर्शन वैसा नहीं रह पाता है।

बोर्ड परीक्षा में एकरूपता लाने का समर्थन करने वाले राज्य अपने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावों पर तेजी से काम कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी राज्य इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे देंगे, जिससे देश के सभी बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता लाई जा सकेगी और इसका सर्वाधिक लाभ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

Visakhapatnam: ABVP stages mock funeral against high educational fees

ABVP activists taking out a protest in Visakhapatnam on 23rd June Visakhapatnam: Opposing the exorbitant fee charged by the private and corporate educational institutions, AkhilBharatiyaVidyarthiParishad (ABVP) staged 'savayatra' (mock funeral procession) depicting education minister BotchaSatyanarayana in Visakhapatnam on 23rd June. The city police reached the protest spot and stopped the activists from proceeding further with their yatra. Speaking on the occasion, ABVP city secretary U Nitin said many parents were struggling due to the existing fee structure and demanded the authorities concerned to suspend the recognition of the institutions that charge unaffordable fees.

The activists further stated that many are disposing of their assets to meet the educational needs of their wards. ABVP district convener

Raju alleged the state government is turning a blind eye towards the institutions that go unchecked with their hiked fee structure. In the name of Olympiad, techno and other tags, the activists pointed out that several managements fleece parents. ABVP representatives Sai Kumar, Satish, Yellaji and others were part of the protest that was interrupted midway due to the police restrictions.

मध्यप्रदेश सात दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन

अखिल भारती विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जबलपुर महानगर द्वारा सात दिवसीय कार्यशाला "गुरुकुल दी विनिंग मंत्र - वन वीक वर्कशॉप ऑन पर्सनेलिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस" का आयोजन किया गया। गत 7 जून से लेकर 13 जून तक नेपियर टाउन स्थित कोजेंट महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, संवाद शैली में निखार, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति जागरूक कराना था।

कार्यशाला में विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, नियंत्रण, संवाद शैली आदि विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला का संचालन प्रो. आत्मानंद दुबे ने किया

और कार्यक्रम के समापन सत्र में अभाविप महाकौशल प्रांत संगठन मंत्री विपिन गुप्ता, मुख्य वक्ता डॉ. नेहा शर्मा (मनोचिकित्सक), प्रांत सह मंत्री सिद्धार्थ गोंटिया, महानगर मंत्री माखन शर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता व प्रतिभागी विद्यार्थी उपस्थित रहे। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)*

प्रशासनिक सक्रियता के कारण विपर्जय चक्रवात से नहीं हुई जनहानि

| अजीत कुमार सिंह |

किसी भी प्राकृतिक आपदा के संबंध में सही सूचना अगर समय पर मिल जाती है, तो आपदा के दौरान होने वाली जन-हानि को आसानी के साथ रोका जा सकता है। कुछ ऐसा ही अरब सागर में आए भीषण चक्रवात विपर्जय के दौरान गुजरात ने कर दिखाया। विपर्जय चक्रवात ने राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्रों में आर्थिक हानि तो पहुंचाई, लेकिन आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन ने जिस तरफ के दूरदर्शी कदम उठाए, उसके कारण किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा विपर्जय चक्रवात के सम्बन्ध में लगाया गया पूर्वानुमान सटीक और निर्धारित आकलन सही रहा। गुजरात सहित अन्य राज्यों को यह सूचना जब मिली तो सबसे पहले गुजरात प्रशासन ने चक्रवात से निपटने की तैयारियां प्रारम्भ कर दी। कारण यह भी था कि विपर्जय चक्रवात का असर सबसे पहले गुजरात के तटीय क्षेत्रों में ही पड़ना था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार विपर्जय चक्रवात अरब सागर में लम्बे जीवनकाल वाले चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया। यह चक्रवात गत 6 जून को प्रातः दक्षिण-मध्य अरब सागर में विकसित होना प्रारम्भ हुआ और फिर 15 जून को सांयकाल कच्छ के जखाऊ तट से टकराया।

चक्रवात की सूचना समय से मिलने के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय तटरक्षक बल सहित राज्य प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों के रूप दर्ज किए गए स्थानों से एक लाख से अधिक लोगों एवं लगभग 78 हजार पशुओं को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, जैसे-बिजली, पेयजल, संचार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं का प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन तो किया ही, साथ ही बड़े वृक्षों की टहनियों को काटने, सड़क पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग को हटाने का कार्य भी हुआ। यही कारण रहा कि विपर्जय चक्रवात ने आर्थिक हानि तो पहुंचाई, लेकिन जन-हानि नहीं हुई। विपर्जय चक्रवात का प्रभाव गुजरात सहित कई राज्यों पर हुआ, लेकिन राज्यों ने अपने स्तर से विपर्जय का सामना किया, जिसमें केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी (पुणे) के वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध में बताया है कि 2001 से लेकर 2019 के मध्य अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में लगभग 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में लगभग 8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान, जलवायु में हो रहे परिवर्तन एवं अरब सागर के ऊपरी हिस्से में वायुदाब में आई कमी आदि चक्रवाती तूफानों में वृद्धि का कारण माने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर क्षेत्रफल की तुलना में बंगाल की खाड़ी से बड़ा है। पहले अरब सागर में चक्रवात के जन्म के सहायक कारकों की कमी रहती थी। लेकिन हाल के वर्षों में तापमान में हुई वृद्धि से अरब सागर के तापमान में लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इसी वजह से अरब सागर के जल का ऊपरी हिस्सा जल्द गर्म होकर जलवाष्प एवं गर्मी पैदा करता है।

विपर्जय चक्रवात के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में अरब सागर के जल के ऊपरी सतह का तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस था। जबकि किसी चक्रवात को विकसित करने के लिए 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की ही आवश्यकता होती है। विपर्जय चक्रवात ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आर्थिक क्षति पहुंचाई, साथ ही मानसून की गति को भी धीमा किया। इस वर्ष अलनीनो के कारण केरल में मानसून का प्रवेश लगभग एक सप्ताह की देरी से हुआ। देरी का कारण भी यही विपर्जय चक्रवात रहा। फ़िलहाल विपर्जय चक्रवात का संकट समाप्त हो चुका है और गुजरात ने जिस तरह से संकट का सामना किया, वह एक मिसाल बन गया है।

विपर्जय चक्रवात से प्रभावित जनता की सेवा में जुटी अभाविप

भारतीय मौसम विभाग द्वारा समय पूर्व विपर्जय चक्रवात की सूचना देने के कारण गुजरात में कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ। चक्रवात से पहले जिस तरह के नुकसान के अनुमान लगाए जा रहे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चक्रवात ने गुजरात के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसके कारण आम जनता को जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे आपत्ति काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गुजरात प्रांत के कार्यकर्ता सामने आए और पीड़ित जनता को भोजन पैकेट, दवाई सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहे।

अभाविप गुजरात के प्रदेश मंत्री कुमारी युति प्रदीप गजरे ने अभाविप के कार्यों के विषय में बताया कि चक्रवात से पहले पूर्व नियोजन के लिए बैठक कर संभावित असर होने वाले जिलों में सेवा कार्य के लिए ठीक से रणनीति तैयार की गयी और फिर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन किया गया। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखा। उसमें भी ज्यादातर नुकसान कच्छ, देवभूमि द्वारका और समुद्र से सटे हुए बाकी जिलों में हुआ। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अभाविप कार्यकर्ता लगातार सेवा कार्य में जुड़े रहे। कार्यकर्ताओं ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि विभिन्न संस्थाएं, संगठन और प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य किया।

पीड़ितों के लिए अभाविप गुजरात द्वारा प्रदेश के विविध और चक्रवात से पीड़ित होने वाले जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। देवभूमि द्वारका के कार्यकर्ताओं ने चक्रवात की संभावनाओं को केंद्र में रखते हुए पूर्व तैयारी के रूप में 15 हजार फूड पैकेट, 500 से ज्यादा रक्तदाताओं की सूची और सैकड़ों कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुड़ने के लिए तैयार किए गए। जिले के कार्यकर्ताओं ने ओखा, सूरजकराडी, खंभालिया, सलाया जैसे विस्तार और गांवों में चक्रवात से प्रभावित लोगों को फूड पैकेट का वितरण किया।

सबसे ज्यादा चक्रवातग्रस्त सूरजकराडी में कंधे तक का जल भराव होने के बावजूद अभाविप कार्यकर्ताओं ने एक किलोमीटर अंदर जाकर फूड पैकेट का वितरण किया। लोगों के उपचार हेतु खंभालिया में सिविल अस्पताल से परिषद के कार्यकर्ता लगातार संपर्क में रहे। कल्याणपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास और भोजन का प्रबंध किया।

प्रदेश के पोरबंदर जिले के कार्यकर्ता भी प्रशासन के साथ सेवाकार्य में जुड़े। पोरबंदर में चक्रवात के कारण स्टेट हाइवे पर कई स्थानों में पेड़ गिरने के कारण आवाजाही बाधित हुई, लेकिन कार्यकर्ता प्रशासन के साथ रास्तों को यथावत स्थिति में लाने के लिए सेवारत रहे। राजकोट महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने सेवाबस्ती और अन्य लोगों के लिए दो दिन के लिए तीनों समय भोजन की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार पूर्वी कच्छ और पश्चिम कच्छ जिले में भी कार्यकर्ता दिन-रात भोजन, दवाई सहित अन्य बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति करते रहे। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)*

Global movement for moderating Islam is inevitable

K N Pandita

Islamic religious leadership has grimly scoffed at movements intending to reform or moderate the Islamic jurisprudence and overall outlook. Opposition of the conservatives in the sub-continent always played the obstructionist. Ijtihad, (reformation), is a significant idea in Shia jurisprudence but the prospect of a consensual opinion among the mujtahids (jurist-consults) has been elusive.

Muslim orthodoxy, unlike other major religions of the world, has been reluctant to reform with the changing times. Fourteen centuries gone in a struggle for change and yet no change in sight, is a bizarre phenomenon. The consequences of a negative approach to the compulsions thrown up by advanced scientific and technological age are unrelenting. Instead of gainfully readjusting to moderate western ways of life, the Muslim clergy advocated rather fiercely distancing from western culture. Two reasons can be imagined. First, the Muslims are fed with the ideology that Islam is the religion sent by Allah to supersede all other religions, and hence, Islamic society (ummah), being different from all other communities, is the superior one and must dominate. The second reason could be the domination of Islamic countries, especially the Arab world, by the western colonizers from 18th to 20th centuries, and controlling their rich resources particularly the hydrocarbon reserves.

We don't say that distinguished brains among the Muslim community did not realize the loss which the ummah will be inflicted owing to senseless apathy and disdain for the western culture. Thinkers like Sir Sayyid Ahmad Khan or Allama Iqbal did rise from time to time in the Indian sub-continent exhorting the ummah to adopt good things of modern western culture. Iqbal brilliantly put forth his ideas on reformation in his scholarly work titled Reconstruction of Islamic Thought. An outstanding Egyptian scholar put the whole narrative in a cryptic but meaningful sentence. Muhammad Abduh came back from Europe so impressed with the order and prosperity he saw that that he told Egyptians: "I went to the West and saw Islam, but no Muslims; I got back to the East and saw Muslims, but no Islam."

The remarkably outstanding Islamic personality of contemporary times, who has drunk deep from the fountain of Islamic knowledge by virtue of being the holder of temporal as well as ecclesiastical authority over the Muslim ummah on the one hand, and on the other has lived and socialised with the western societies for many years, is Crown Prince Muhammad bin Salman, lovingly called MBS by his western friends and associates. No Islamic leader of our times has as deep an understanding of the need for drastic reforms in Islam as he has. Being in a position of authority and driven by a vision of the future of the ummah, he has already undertaken several measures of pulling the Muslim societies out of a morass of antiquated and obsolete practices and traits that have caused the backwardness and segregation of the ummah in an overall estimation. It is an irony that a country which meets one-third of world's oil requirement should remain steeped in conservatism and backwardness of the Middle Ages.

The Crown Prince's lead has inspired many of his close associates and compatriots to initiate a reformation movement aiming at converting the stereotyped Islam to a moderate, vibrant and inclusive Islam. He is fully aware that under political compulsions, contemporary Muslims want realization of their aspirations. The failure to argue their point effectively has led them to resort to violence oblivious of dire and disastrous consequences of an adventure like that.

Today, we find that if every Muslim is not a terrorist but every terrorist is a Muslim. We find that the largest religious community in the world that has bid farewell to its native land and migrated to a western country to earn two square means in an environment of peace, tranquillity and justice is that of the Muslims. Why is it so? The malaise lies in politicising Islam.

These questions have upset the mind of the emancipated and visionary leader of Saudi Arabia. We have a special reason to appreciate his courage and determination to initiate much-needed reforms in Islamic jurisprudence. Prince Salman is a firm believer in resolving disputes and differences through dialogue and a votary of non violence. He has taken some important measures to resolve Yemen dispute and strongly supported invitation to President Assad of Syria for participation in the Islamic summit meet in Riyadh.

Eminent Islamic scholar, Dr Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa from Saudi Arabia, Secretary General of Muslim World League cited as one of the strongest global voices on moderate Islam is in India. He addressed prominent religious leaders, scholars and academics in the capital on Tuesday. He shared the stage with NSA Ajit Doval, who also addressed the gathering at the India Islamic Cultural Centre (IICC).

In his interface with Indian intellectuals and luminaries at various levels and meetings, Al-Issa is expected to speak on a wide range of issues ranging from moderate Islam, dialogue between civilizations, religious tolerance, intercultural communication, non-violence and religious pluralism. Ahead of the visit, IICC president Sirajuddin Qureshi had described this "coming together" of Al-Issa and Doval for the special address on Tuesday as a moment that promises to send out a strong message to the world. "We see this special address as a moment that will bolster the message of inter-faith harmony and national integration," Qureshi said. This programme was organised by the NGO Khusro Foundation and IICC. Qureshi said invitations had been sent to not just prominent Muslim religious leaders and scholars but also those from other religions.

It is a matter of great satisfaction that a leading religious scholar and ideologue from the heartland of Islam holding the high position of Secretary General of Muslim World League, has chosen to speak in India for the dissemination of crucial themes like dialogue between civilizations, religious tolerance, intercultural communication, non-violence and religious pluralism. These are the themes which our Islamic theologians generally evade or not feel comfortable with. It is a unique event that an Islamic divine from Saudi Arabia is speaking on topics like these.

India is the second country in the world with the largest number of Muslim population after Indonesia. The significance of India is that this second Muslim populated country is a democratic and a secular country where we have the people of almost all existing faiths in the world and they are all treated on an even keel.

Seven and a half decades ago, on the eve of their departure, the colonialists divided India on the basis of religion. This unnatural act is the greatest holocaust one can recall in the history of mankind. Its scars are still festering. Nearly three decades later,

the separated part got further divided into two not on religious but ethnic grounds. The foolhardiness of the inhuman act of dividing countries on religious basis has left behind a mindset muddied by deep-seated hatred and animosity. All attempts of healing those scars are made ineffective through a vicious and malignant propaganda and also by waging a proxy war. India's secular democracy is threatened because the perpetrators of a proxy war have failed to establish and strengthen the concept of democracy in their land. Waging a state-run proxy war has necessitated the creation of home-bred terrorist organizations to be labelled as jihadists waging a religious war against secular democracy.

The distinguished guest is the first top Islamic scholar of great eminence who is talking on issues that the Muslims of contemporary times must discuss and come to the final conclusion that this earth is created for the use of people of all faiths and views to live in harmony and not in antagonism. His message resounds after the voice of our constitution. This could be a watershed in the history of Islam in the sub-continent, and an ethical as well as juridical message to the Muslim population of India. Moderating Islam is the guarantee for the prosperity and perpetuation of Islam in India. The visit of the distinguish guest should not be linked to any political goal. The message is immensely beyond mundane political objectives. ■

(A prominent Islamic scholar and reformist, Al-Issa, before being appointed secretary general of the Muslim World League (a non-government organisation representing the community worldwide) in 2016, Al-Issa served as the minister of justice in the Saudi Arabian cabinet. During his tenure, he oversaw key reforms in several areas, including legislative reforms in family matters, humanitarian cases, and women's rights.)

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक को स्वीकृति देने का निर्णय स्वागतयोग्य : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय का स्वागत किया है। अभाविप का मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में शोध कार्य को बढ़ावा व इससे संबंधित अवसंरचना के विकास हेतु शीघ्र प्रयास करना बहुत आवश्यक है। आज वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के युग में शोध संस्कृति का उन्नत होना काफी महत्वपूर्ण है, जिसको इस विधेयक के संसद में पारित होने से बल प्राप्त होगा।

जानकारी हो कि अभाविप शोध संस्कृति को उन्नत बनाने, संबंधित अवसंरचना को विकसित करने तथा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान को समावेशी बनाने की मांग केन्द्र सरकार से लगातार कर रही थी। अभाविप का मानना है कि यह प्रतिष्ठान देश में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला होगा। अभाविप आशान्वित है कि संसद में इस विधेयक के पारित होने के बाद देश में अनुसंधान एवं विकास के मसले पर उद्योग जगत द्वारा सहयोग तथा आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए सभी हितधारक मिलकर प्रयास करेंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम नज़र आएंगे।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के अनुसार देश में अनुसंधान संस्कृति का बेहतर होना और शोध कार्य हेतु मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता बेहद आवश्यक है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना से उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में सशक्त अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास किया जा सकेगा। अभाविप इस विधेयक को संसद द्वारा जल्द पारित करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आशान्वित है। ■

अभाविप आयाम जिज्ञासा द्वारा आषाढ़वारी चिकित्सा सेवा-2023 का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आयाम जिज्ञासा द्वारा पश्चिम महाराष्ट्र में आषाढ़वारी चिकित्सा सेवा-2023 का आयोजन किया गया। निःशुल्क चिकित्सा सेवा का आयोजन जिज्ञासा पश्चिमी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र विज्ञान विद्यापीठ, नासिक के संयुक्त तत्त्वावधान में किया गया। जिज्ञासा कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आषाढ़वारी वैद्यकीय सेवा उपक्रम-2023 के अंतर्गत निगड़ी, पुणे, सासवड़, बारामती, लोणंद, तरडगांव, फलटण, इंदापुर, माळशिरस, अकलूज, वेलापुर और वाखरी जैसे स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिसमें 70 से हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने चिकित्सा सेवा का लाभ लिया।

अभाविप आयाम जिज्ञासा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत सात वर्षों से जिज्ञासा के द्वारा आषाढ़वारी में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अग्निकर्म, विधकर्म जैसी चिकित्सा पद्धतियों का विशेष शिविर भी लगाया जाता है। जिज्ञासा टीम द्वारा व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, व्यसनों, अंगदान के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सा के साथ-साथ, नुक्कड़ नाटक को ग्रामीण भाषा में उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आम नागरिक सहज रूप से समझ सके। महिलाओं में अधिक मात्रा में होने वाले एनीमिया जैसे रोग के बारे में मूलभूत जानकारी, कारण, आहार एवं सावधानियों के पत्रक बांटे जाते हैं। इस वर्ष महाराष्ट्र के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 765 से अधिक मेडिकल छात्रों एवं डॉक्टरों ने शिविर में सेवा प्रदान की। जिज्ञासा कार्यकर्ताओं के अनुसार समाज के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक जागरुकता सभी के मन में है, लेकिन चिकित्सा पेशे में सेवा शिविर की शुरुआत आमजन के ज्ञान का उपयोग कर जन-जन तक पहुंचाने के लिए की गई है।

जानकारी हो कि आषाढ़वारी महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा का शिखर है। आषाढ़वारी (पंढरपुर) आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वारकरी भक्तों द्वारा पंढरपुर तक की जाने वाली तीर्थयात्रा है। यह यात्रा महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों से प्रारम्भ होकर पंढरपुर में समाप्त होती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह पर्व हरिनाम संकीर्तन एवं शुद्ध भक्ति का ही पर्व है। आषाढ़ चढ़ते ही पांडुरंग परमात्मा के दर्शन के लिए असंख्य तीर्थयात्री कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। वर्ष की सबसे बड़ी इस यात्रा में विट्ठल भक्त नजर आते हैं और पंढरपुर में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इसे आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए इस तीर्थ स्थल का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस आषाढ़ी एकादशी के दिन से विट्ठल की नींद शुरू होती है और इसी दिन से चातुर्मास की पवित्र अवधि शुरू होती है। इस अवधि के दौरान भक्त विठ्ठल की पूजा में जितना संभव हो उतना समय बिताते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दौरान मंदिर सभी भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

'परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 की रिपोर्ट ने खोली दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की पोल'

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का दावा करते हुए दिल्ली की आप सरकार विश्वस्तरीय शिक्षा, विश्वस्तरीय स्कूल और विश्वस्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए स्वयं देखी जा रही है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार के दावों की पोल खुलने लगी है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 (पीजीआई-2.0) 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सातवीं श्रेणी को रखा गया है।

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंतर्गत बनाई गई दस श्रेणियों में से 7वें स्थान में आने से आप सरकार के दावों का सच तो सामने आए ही, साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि गत कुछ वर्षों के दौरान भले ही अधिकतर बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने का कार्य तो हुआ, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में दिल्ली सरकार अन्य राज्यों से बहुत पीछे है।

परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 (पीजीआई-2.0) 2021-22 की रिपोर्ट में चंडीगढ़ और पंजाब को देश में पहला स्थान मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने में चंडीगढ़ और पंजाब सबसे आगे हैं। छह मापकों और 73 सूचकों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में 1000 में से चंडीगढ़ ने 659 और पंजाब ने 647.4 अंक प्राप्त किए हैं। एक्सेस मापक में अर्थात शिक्षा उपलब्ध कराने में 68.6 अंक प्राप्त कर चंडीगढ़ दूसरे ग्रेड और 62.1 अंक लेकर पंजाब तीसरे ग्रेड पर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 रिपोर्ट में लर्निंग आउटकम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मानक में भले ही चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान सबसे अधिक अंकों से शीर्ष पर हैं, लेकिन इन राज्यों का प्रदर्शन भी दस श्रेणियों में छठी श्रेणी में ही स्थान हासिल कर पाया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आउटकम और गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत छह मापकों और उनके 73 सूचकों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के लिए यूडाईस प्लस, एनएएस, पोषण पोर्टल, प्रबंध और विद्यांजलि पोर्टल से डाटा लिया गया। 2017 से तैयार हो रही पीजीआई इंडेक्स को अबकी बार परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 का नाम दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति का नया मापक भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही चौथे सतत विकास लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा को शामिल किया गया, जिसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा का स्तर, स्कूल में उपलब्ध सुविधा और बेहतर शिक्षा का आकलन किया गया है।

परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 रिपोर्ट में अंकों के अनुसार दस ग्रेड बनाए गए हैं, जिसमें न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी-3 और ऊपरी ग्रेड दक्ष है। चंडीगढ़ और पंजाब पीजीआई इंडेक्स में ओवरऑल छठे ग्रेड अर्थात प्रचेष्टा-2 पर रहे। इसके विपरीत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने लगातार दूसरी बार अपना रिकॉर्ड कायम रखा। हालांकि चंडीगढ़ का स्कोर पंजाब से अधिक है, लेकिन दोनों इंडेक्स के छठे ग्रेड पर हैं। तथ्य यह भी है कि रिपोर्ट में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने में पंजाब और चंडीगढ़ का स्कोर सबसे कम है।

जानकारी के अनुसार लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है, जिसके अंतर्गत तीसरी, पांचवी, आठवीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई के स्तर का आकलन किया गया। लर्निंग आउटकम में चंडीगढ़ ने 103.6 और पंजाब ने 113.4 अंक प्राप्त किए। पंजाब में गवर्नमेंट प्रोसेसेज के साथ आधारभूत संरचना मापक पर अंक सबसे कम रहा। उसका स्कोर 70.3 और 102.3 रहा। रिपोर्ट में पहली बार शामिल किए टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग मापक में चंडीगढ़ ने 84.7 और पंजाब ने 72.2 अंक प्राप्त कर दूसरा और तीसरा ग्रेड हासिल किया। स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन के निर्धारण के लिए पहले पांच मानक और आठ श्रेणियां थी, जिनमें शिक्षा मंत्रालय ने अबकी वर्ष छह मानक और दस श्रेणियां तैयार की। इसमें स्कूली शिक्षा को भी जोड़ा गया है। इंडेक्स में

सरकारी कामकाज के आधार पर दिए वाले वेटेज (अंकों) को कम कर दिया गया है।

परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 रिपोर्ट में जहां टॉप 5 श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं है, तो छठी श्रेणी यानि प्रचेष्टा-2 में पंजाब और चंडीगढ़, सातवीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा-3 में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पुंडुचेरी, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। ओवरआल रैंकिंग की आठवीं श्रेणी यानी आकांक्षी-1 में 13 राज्य, क्रमशः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दादर नगर हवेली को रखा गया है। इसी प्रकार नौवीं श्रेणी यानी आकांक्षी-2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखण्ड सहित 12 राज्य शामिल हैं।

परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 रिपोर्ट ने देश की राजधानी में शिक्षा स्तर में किए जाने वाले आप सरकार के दावे के सच को सामने रखा है। जबकि इससे पहले राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के कुपोषित होने जानकारी सामने आयी थी। शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली के एक हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में कराई गयी जांच में चार लाख से अधिक बच्चों का वजन सामान्य से बहुत कम पाया गया था। बच्चों को भरपूर पोषण न मिलने के कुपोषित होने के इस मामले में गंभीर बात यह भी है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में मिड-डे मील के तहत बेहतर और पोषित भोजन दिए जाने का दावा आप सरकार लगातार करती आ रही है।

देश के अंदर मिड-डे मील योजना चलाने का उद्देश्य बच्चों को सही और पोषित आहार देने का है, जो उनके स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खराब पोषण से बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे वह शिक्षा में कमजोर रह जाते हैं। इस प्रकार देखें तो दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाने का दावा पूरे देश में किया जा रहा है, वह भ्रामक है। साथ ही जमीनी आधार पर वास्तविक आकलन पर बनने वाली रिपोर्ट दिल्ली सरकार के दावों का वास्तविक सच जनता के सामने लगातार ला रही हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

त्रिपुरा

छात्रा के साथ सहायक प्राध्यापक ने की अभद्रता, सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अभाविप ने किया प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने त्रिपुरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के विरुद्ध त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मौखिक परीक्षा के दौरान एक छात्रा के साथ सहायक प्राध्यापक की अभद्रता के विरोध में किया गया।

अभाविप त्रिपुरा के प्रदेश मंत्री संजीत साहा ने बताया कि दर्शनशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर प्रो. भूपेश देबबर्मा ने एक छात्रा को यौन और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया। कथित घटना दर्शनशास्त्र की मौखिक परीक्षा के दौरान हुई। घटना से सदमे में आई छात्रा बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभाविप ने कुलपति से आरोपी प्राध्यापक को तत्काल निलंबित कर उस पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर दोषी प्राध्यापक पर कार्रवाई नहीं करेगा तो परिषद कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।

उधर पीड़िता के परिवार ने सहायक प्राध्यापक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अमतली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने मौखिक परीक्षा के दौरान कई अभद्र प्रश्न किया और उसके साथ छेड़छाड़ भी की। बाद में सहायक प्राध्यापक ने छात्रा को धमकी देते हुए कहा कि वह इस मामले के बारे में किसी को न बताए। पीड़िता के परिवार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)* ■

अभाविप ने देश के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया

योग-जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग हमारे शरीर, मन और भावना को स्थिर और नियंत्रित भी करता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना यहां अभीष्ट है। योग की पूर्णता इसी में है कि जीव भाव में पड़ा मनुष्य परमात्मा से जुड़कर अपने निज आत्मस्वरूप में स्थापित हो जाए। इस संदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के खेल गतिविधि आयाम द्वारा देश भर के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। अभाविप द्वारा आयोजित योगाभ्यास में प्राणायाम के विभिन्न क्रियाओं एवं सूर्य नमस्कार का विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की एवं योग की विभिन्न क्रियाओं को सीखा एवं अभ्यास किया।

दिल्ली में खेल आयाम गतिविधि द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय, दौलत राम कॉलेज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अन्य 50 शैक्षणिक स्थानों ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभाविप द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में उपस्थित युवाओं को योग प्रशिक्षकों ने नियमित योग करने के गुण सिखाए तथा उन्हें योग के प्रति जागरुक भी किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम महाविद्यालय में योग कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अभाविप के खेल आयाम गतिविधि के राष्ट्रीय प्रमुख प्रदीप शेखावत ने कहा कि विश्व योग दिवस के अवसर पर भारत की शक्ति आज पूरे विश्व में देखी गई। योग हमारे तन और मन दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको ध्यान में रखते हुए योग बहुत आवश्यक है। युवाओं को समय निकालकर योग करना चाहिए, जिससे दैनिक जीवन-शैली में सकारात्मक परिवर्तन आ सकें। अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने बताया कि आज

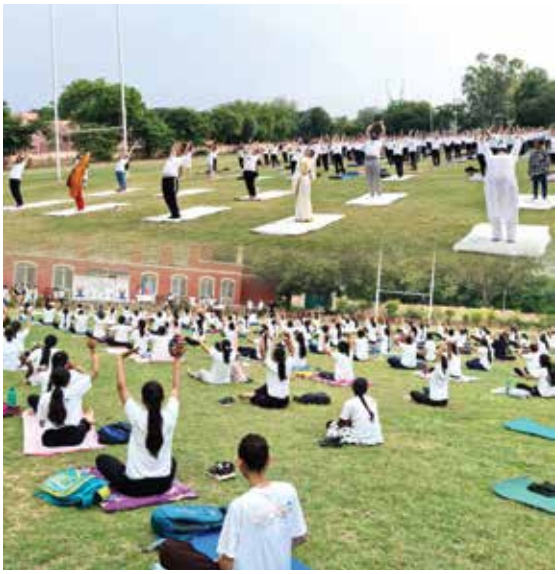

हमने योग दिवस व्यापक स्तर पर मनाया, जिसमें हमने विभिन्न शैक्षणिक स्थानों पर वहां के छात्रों के साथ योग किया। योग हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। सारे विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में योग नियमित तौर पर कराना चाहिए ताकि देश के युवा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकें।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अंबेडकरनगर में अभाविप अवध प्रांत अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस अवसर पर अभाविप पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने कहा कि योग कई सदियों से भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। भारत की पहल पर योग के महत्व को देखते हुए इसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया है। योग का सबसे पहला उल्लेख सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। कोरोना काल में दुनिया को योग और आयुर्वेद ने महामारी को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ABVP protests in School of Open Learning (SOL) regarding various educational demands

ABVP demands formation of examination department for permanent solution of problems of SOL students

New Delhi - The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad on Wednesday staged a vigorous protest outside the Examination Department of Delhi University regarding various educational demands of SOL, and handed over a memorandum to the university administration demanding the timely fulfillment of the demands. Students of SOL have been facing various problems related to examinations and results for a very long time, for which ABVP has also demanded from the administration to constitute a separate examination department for SOL.

SOL (School of Open Education) affiliated to the University of Delhi is a center of distance education. In which a large number of students study, but due to the negligence of the administration, the students studying here have to face several problems. Taking cognizance of these problems, ABVP today organized a march from SOL Main Gate to the Examination Department and demonstrated a huge protest in front of the Examination Department. ABVP handed over a memorandum to the Examination OSD Ajay Arora to declare the semester results as soon as possible, to fix the errors in the results, to set up a separate examination department to solve the problems faced in the examination and demanded to conduct a special exam for the failed students.

Students informed that more than two weeks has passed since the first semester results of NCWEB and Regular college going students were declared, while the results of first semester students of SOL have not been declared yet. Similarly, the results of the sixth semester students are also stuck in limbo while admissions for post graduation have started in all the institutes. If the result does not come on time, then the students of the sixth semester will be deprived of taking further admission in post graduation, and their academic year will be ruined. Admit cards are being issued within a day or two before the examinations due to which the students have to face huge inconveniences. There are various irregularities in the results, which the student himself has to get rectified by running around the administrative offices. Students said that there are more students in SOL than in regular institutions of Delhi University, yet such problems are also happening due to the absence of any separate examination department in SOL. Therefore ABVP has also demanded from the administration to set up a separate examination department in SOL.

Raj Anand, secretary of SOL unit of ABVP, who was present during the protest, said that SOL is a distance learning and part-time learning center for students, in which a large number of students from different areas of Delhi come to study, but due to the carelessness and wavering attitude of SOL administration, the students are facing various academic problems; therefore, they are not able to continue their studies regularly and smoothly. Keeping all these problems in mind, today we protested and put our demands before the administration and demanded to fulfill the demands as soon as possible. We have demanded the administration to solve the current problems of the students immediately, and to set up a separate examination department, to ensure a permanent solution to the problems faced by the students. ■

अभाविप ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव, दिल्ली में चल रहे कोचिंग संस्थानों के नियमन की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के नेतृत्व में दिल्ली के छात्रों ने सैंकड़ो की संख्या में चल रहे कोचिंग संस्थानों के नियमन सहित विभिन्न मांगों को लेकर गत 27 जून को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया। अभाविप ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार छात्र विरोधी है। वह शहर के कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी नियमों को लागू करने में लापरवाही बरत रही है। जानकारी हो कि गत 15 जून को दिल्ली के कोचिंग हब मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गयी थी, जिसमें 70 छात्र घायल हुए थे।

अभाविप ने मुखर्जी नगर कोचिंग संस्थान अग्निकांड में घायल छात्रों को मुआवजा देने, दिल्ली में बेतहाशा बढ़ रहे कमरों के किरायों को नियंत्रित करने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करने, फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की मांग लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार की शिक्षा क्षेत्र व प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं को लेकर अनदेखी से गुस्साए छात्रों ने लगभग एक घंटे तक महात्मा गांधी रोड को जाम करके समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित दिल्ली के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों के सैकड़ों छात्रों सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने सहभागिता की। प्रदर्शन के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

बाद में अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना के बाद हुई जांच से स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश कोचिंग संस्थान बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं। यह दिल्ली सरकार की लापरवाही को दिखाता है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए बोर्ड गठित किया जाए और बिना मानक चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो। छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

अभाविप दिल्ली की प्रांत छात्रा प्रमुख व डूसू सह-सचिव शिवांगी खरवाल ने कहा कि दिल्ली में कमरों के बढ़ते किराए व मनमानी के कारण छात्रों को बहुत समस्याएं हो रहीं हैं। कमरों के किराए को नियंत्रित

करने के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए, जिससे अप्रत्याशित किराया वृद्धि को रोका जा सके। दिल्ली सरकार एक तरफ तो शिक्षा की बेहतरी की बात करती है, परंतु दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र परेशानियों से जूझ रहे हैं। उस पर दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर दिल्ली सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम फिर प्रदर्शन को बाध्य होंगे।

कोचिंग में आग लगने पर विद्यार्थियों ने तीसरी मंजिल से कूदकर बचाई थी अपनी जान

गत 15 जून को दिल्ली के बत्रा सिनेमा के पास एक ईमारत में दोपहर 12 बजे आग लग गई थी। इस ईमारत में कोचिंग सेंटर चल रहा था। जान बचाने के लिए छात्र ईमारत की तीसरी मंजिल से तार के सहारे नीचे उतरे थे। कुछ ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई थी। हादसे के बाद 61 लोगों को इलाज के लिए तीन अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। हादसे के दौरान 200-250 छात्र मौके पर मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में यह बताया गया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के मीटर में आग लगी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार व नगर निगम को भेजा नोटिस

अग्निकांड के इस मामले को लेकर गत 16 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खुद ही हस्तक्षेप किया। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, स्टेट फायर सर्विस, नगर निगम और स्थानीय पुलिस को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण देने को कहा था। मामले में न्यायालय ने कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटनाओं, फायर सर्विस डिपार्टमेंट से कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने का भी निर्देश भी दिया था। जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा था कि न्यूज पेपर्स में छपी खबर के आधार पर हम घटना पर खुद ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)* ■

ओड़िशा

रथयात्रा में आए श्रद्धालुओं के लिए सेवा कार्य में जुटे अभाविप कार्यकर्ता

जगन्नाथ पुरी की विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा में आए श्रद्धालुओं की सेवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कार्यकर्ता दिन-रात डटे रहे। अभाविप ओड़िशा प्रांत के मंत्री अरिजित पटनायक ने बताया कि रथ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, वह भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी के रथ का सुगम तरीके से दर्शन कर सके, इस हेतु तैयारी एक माह पहले से ही प्रारम्भ कर दी गई थी। रथ यात्रा में पूरे प्रांत से 700 से अधिक कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य के लिए बुलाया गया। गत 20 जून अर्थात रथयात्रा के एक दिन पहले इन सभी का मॉक ड्रील भी कराया गया।

जानकारी हो कि हर वर्ष जगन्नाथ पुरी में होने वाली रथयात्रा में भाग लेने के लिए देश भर के लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हो, जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ मिलकर ट्रैफिक का संचालन भी किया। साथ ही अभाविप ने तीन किलोमीटर का ग्रीन कोरिडोर बनाया, जिससे एंबुलेंस की आवाजाही में कोई समस्या नहीं पैदा होने पाई। यात्रियों के उपचार के लिए मेडिविजन के द्वारा सेवा शिविर का आयोजन भी किया गया। विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए कार्यकर्ताओं ने हेल्प डेस्क बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में परिषद कार्यकर्ता अस्पताल में मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान पवित्रता बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं की कुछ टोली सफाई कार्य में भी जुटी रही। अभाविप प्रांत मंत्री अरिजित पटनायक ने बताया कि कोरोना काल को छोड़ दे तो वर्ष 2015 से ही रथयात्रा के दौरान सेवा कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रांत भर के कार्यकर्ता सहभागी होते हैं। अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने अभाविप कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने रथयात्रा पर एक ब्रोसर का विमोचन भी किया। इस दौरान अभाविप क्षेत्रीय संगठन मंत्री अपांग्शु शेखर सील, प्रांत अध्यक्ष गार्गी बनर्जी, प्रांत संगठन मंत्री बैलोचन साहू, प्रांत मंत्री अरिजीत पटनायक सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर अभाविप का प्रदर्शन, उच्च शिक्षा मंत्री ने दौरा रद्द किया

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गोरखपुर महानगर द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद अभाविप ने विश्वविद्यालय कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया। विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता सहित पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उत्पन्न हुई शैक्षिक समस्याओं को लेकर अभाविप ने उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय का घेराव करने की घोषणा की थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने अपना गोरखपुर दौरा रद्द कर दिया।

अभाविप गोरक्ष प्रांत राज्य विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख ऋषभ सिंह के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रमों में विषय पूर्ण नहीं होने के बावजूद उनकी भी परीक्षाएं करायी जा रही है। गंभीर मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय में कक्षाओं का संचालन उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों से न कराकर शोध विद्यार्थियों से कराया जा रहा है, जिसे तत्काल बन्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाएं तो समय से हो रही हैं, परंतु छात्रों को उनके पिछले सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का निरस्त होना सामान्य सी बात हो गयी है, जिससे छात्रों को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में स्वच्छता और प्रसाधन की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिसकी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हैं। अभाविप ने मांग की है कि विश्वविद्यालय में लगे वाई-फाई को अतिशीघ्र चालू किया जाए। साथ ही आगामी सत्र में प्रवेश हेतु होने वाली प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी भी विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द जारी करे। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि आगामी सत्र में छात्रसंघ के चुनाव को समय से संपन्न कराया जाए। साथ ही दस दिन में डिग्री उपलब्ध करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पुस्तकालय की ख़राब स्थितियों को ठीक करने और नियमों को ताक पर रखकर हो रही सहायक आचार्य भर्ती की जांच कराने की मांग भी की है।

अभाविप के गोरक्ष प्रांत संगठन मंत्री हरिदेव के अनुसार विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के विरोध में परिषद ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में

आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय का घेराव करने का निर्णय लिया था। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री ने गत 28 जून को गोरखपुर जनपद का अपना प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि परिषद अपनी पूरी शक्ति के साथ छात्र हितों के प्रति समर्पित भाव से काम कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन को बाध्य कर देगी, जिससे विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप (पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र) का दो दिवसीय क्षेत्रीय प्राध्यापक वर्ग संपन्न

शिक्षकों से राष्ट्र प्रथम भाव के साथ आगे आने की अपील

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का दो दिवसीय क्षेत्रीय प्राध्यापक वर्ग गत 29-30 जून को गोकुल अतिथि भवन, गोरखपुर में संपन्न हुआ। दो दिन तक चले वर्ग में विभिन्न सत्र को संचालित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए शिक्षकों ने संगठन और समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया। क्षेत्रीय प्राध्यापक वर्ग को संबोधित करते करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही ने कहा कि अभ्यास वर्गो के माध्यम से हम साधना से सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। शिक्षकों को राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर आगे आना होगा क्योंकि शिक्षा को आनंदमय प्रक्रिया बनाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं।

उन्होंने कहा कि अभाविप ही एक ऐसा छात्र संगठन है, जिसमें शिक्षक और छात्र कार्यकर्ता दोनों मिलकर एक-साथ संगठन कार्य करते हैं। शिक्षक कार्यकर्ता को हमें स्थायी कार्यकर्ता बनाना होगा, जिनके उचित मार्गदर्शन में संगठन कार्य का और अधिक विस्तार हो सके। उन्होंने कहा कि यह सदी भारत की सदी है। भारत की सदी केवल अपने देश की ही नही, अपितु दुनिया की सदी होगी। आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ऐसे में अपने देश के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हमें यह सुनिश्चित करना होगा।

इस अवसर पर अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य संचित होने पर ही कोई शिक्षक बनता है। आज इस समाज को चाणक्य जैसे शिक्षकों की आवश्यकता है। अध्यापक का कार्य आजीविका प्राप्त करना ही नही है, बल्कि यह एक उच्च आदर्शपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि अभाविप के साथ जुड़ने पर यह कार्य और अधिक दायित्वपूर्ण व महान हो जाता है। अभाविप एक महासागर है, इसमें हम जितना गहराई में जाते है, उतनी और अधिक गहराई नजर आती हैं। अभाविप में हमारी भूमिका सहयोगी सदस्य की होती हैं, जहां हमारे कर्तव्य असीमित है, किंतु हमारे अधिकार शून्य हैं।

बिहार में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में अभाविप ने किया प्रदर्शन

शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण : अभाविप

बिहार में दशकों से चली आ रही डोमिसाइल नीति को हटाने, शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उन पर लाठीचार्ज जैसी बिहार सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बिहार ने राज्य स्तरीय धरना देकर अपना रोष प्रकट किया। अभाविप ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन के बाद दशकों से चली आ रही डोमिसाइल नीति को हटाकर लगभग एक दर्जन संशोधन कर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को हाशिए पर धकेल दिया है। राज्य सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं में निराशा का माहौल है।

राजधानी पटना के गर्दनीबाग में गत 7 जुलाई को आयोजित राज्यस्तरीय धरना-प्रदर्शन में अभाविप बिहार के प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाया गया है। सरकार में बैठकर शिक्षा माफियाओं के इशारे पर राज्य के छात्रों के लिए तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। छात्र अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर लाठी चलाई जाती है। यह एक तानाशाही एवं संकीर्ण सोच वाली सरकार की मानसिकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री खुद यह कहकर जंगल राज की पोल खोल रहें है कि बिहार में उनके द्वारा 15 वर्षों तक शिक्षा में क्या काम हुआ कि उन्हें योग्य शिक्षक नही मिल रहे हैं। सरकार के विरुद्ध विद्यार्थी परिषद ने राज्य स्तरीय धरना का आयोजन करके सरकार से मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। अगर बिहार प्रदेश शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो बिहार के एक-एक घर से निकल कर छात्र-युवा आंदोलन का बिगुल विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बजा देंगे।

धरने को संबोधित करते हुए परिषद के केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान बिहार सरकार अपने मंत्रालयों में ही तालमेल नहीं बिठा पा रही है और अलोकतांत्रिक एवं तानाशाह वाले फैसले छात्रों के लिए ला रही है। डोमिसाइल नीति बिहार के छात्रों का अधिकार है। हर राज्य सरकार अपने-अपने प्रदेश के छात्र और युवाओं के हितों में डोमिसाइल नीति को लागू की है। लेकिन बिहार सरकार द्वारा बिहारी छात्रों के हित में यह फैसला को लागू नहीं करना, यह दर्शाता है कि शिक्षा माफियाओं के सहारे अवैध वसूली का खेल शुरू करने के लिए यह कदम उठाया गया। अभाविप राज्यव्यापी धरने के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि डोमिसाइल नीति को अविलंब संशोधन करके बिहार के छात्र हित में निर्णय लिया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद सड़क से सदन तक प्रदर्शन करेगी।

इस अवसर पर अभाविप बिहार के प्रांत संगठन मंत्री धीरज कुमार ने कहा कि सरकार अगर डोमिसाइल नीति पर जल्द निर्णय नही लेती है, तो अभाविप राज्य व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगी। पूरे राज्य से अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा मार्च कर राज्य सरकार के विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। अभाविप सह छात्रा प्रांत प्रमुख प्रतिभा मिश्रा ने शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। वहीं, प्रदेश सह मंत्री सुरज सिंह ने राज्य की छवि को धूमिल करने वाले राज्य के शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफ़ा देने की मांग की। पूर्व प्रदेश मंत्री भरत सिंह जोशी ने कहा कि राज्य की सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। इस निद्रा से जगाने के लिए अभाविप पुनः बिहार के युवाओं के साथ अपने अधिकार की मांग के लिए विधान सभा कूच कर उन्हें जगाने का काम करेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पटना : बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति के विरोध में धरना–प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

दिल्ली : कोचिंग संस्थानों के नियमन सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते अभाविप कार्यकर्ता

RNI NO.: DELBIL/2017/73636 POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

पर्यटन
के नए क्षितिज पर
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश पर्यटन

यू.पी. नहीं देखा,
तो इंडिया नहीं देखा...

डबल इंजन की सरकार, विकास की दोगुनी रफ़्तार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश